04 - सवैधानिक संस्था का अपमान सुनियोजित?

05 - सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक

A Daily News Magazine
इंदौर
सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025

06 - वृद्धजनों ने नर्मदा दर्शन व स्नान का लाभ पाया, पांचवी आनंद यात्रा महेश्वर...

07 - सीहोर जिले में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 31, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या यह 'कॉरपोरेट मुनाफाखोरी' के आरोप पर आरबीआई की मुहर है?

पंकज श्रीवास्तव

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉरपोरेट सेक्टर पर बड़े पैमाने की लूट का आरोप लगाया था। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले तीन सालों में कॉरपोरेट सेक्टर का मुनाफा ज़बर्दस्त बढ़ा है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की एक रिपोर्ट भी बता रही है कि इस समय कॉरपोरेट मुनाफ़े ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। आरबीआई की अक्टूबर बुलेटिन के मुताबिक़ कोविड के बाद बीते चार सालों में कॉरपोरेट मुनाफ़ा तीन गुना बढ़ा है। यह सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 फ़ीसदी तक पहुँच गया है जो 17 सालों में सर्वाधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक़ वित्तीय वर्ष 2020-21 में कॉरपोरेट्स का कुल मुनाफा (नेट प्रॉफिट) 2.5 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 तक बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपये हो गया - यानी लगभग तीन गुना। कॉरपोरेट मुनाफे में यह उछाल कई कारकों का नतीजा है-

दबी हुई माँग: कोविड के बाद लोगों ने खरीदारी बढ़ाई, जिससे बिक्री में तेजी आई, खासकर 2021-22 में।

लागत प्रबंधन: कंपनियों ने ऑटोमेशन और दक्षता बढ़ाकर खर्च कम किया।

सरकारी नीतियाँ: कॉरपोरेट टैक्स में कटौती (2019 में 30% से 22%), कम ब्याज दरें, और प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम ने कंपनियों को राहत दी।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जो देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। कॉरपोरेट मुनाफा से जीडीपी अनुपात (Corporate Profit to GDP Ratio) बताता है कि देश की कुल कमाई का कितना हिस्सा कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 327.7 लाख करोड़ रुपये (लगभग USD 3.91 ट्रिलियन) है। आरबीआई के अनुसार, कॉरपोरेट मुनाफा जीडीपी रेशियो 4.7% है, जो 17 सालों में सबसे ऊँचा स्तर है। इसका मतलब है कि 15.40 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट मुनाफे के रूप में जा रहा है।

एक नज़र में कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफ़ा समृद्धि की ओर इशारा करता है लेकिन क्या इससे देश के आम लोगों के हालात बदल रहे हैं? मुनाफा मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों (जैसे बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी) तक सीमित है, और छोटे व्यवसायों या आम आदमी को इसका सीधा फायदा नहीं मिल रहा। विपक्ष इसे 'कॉरपोरेट लूट' कहता है और मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि वह कॉरपोरेट जगत का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए नियमों के साथ भी खिलावड़ करती है। कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था- 'मोदी सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। इतने पैसे से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की नौकरी मिल सकती थी, 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देकर उनके परिवारों का जीवन बदल सकता था। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ करके अनगिनत आत्महत्याओं को रोका जा सकता था। पूरे देश को 20 साल तक सिर्फ 400 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा सकता था। भारतीय सेना का पूरा खर्च 3 साल तक वहन किया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त की जा सकती थी। ज्जो धन 'भारतीयों' के दर्द को दूर करने में खर्च किया जा सकता था, उसे 'अडानी' जैसे लोगों के लिए प्रचार करने में खर्च किया गया।'

भारत में असमानता तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब (2024) और ऑक्सफैम की "Survival of the Richest: The India Story" (2023, 2024 अपडेट) के अनुसार: शीर्ष 1%: 22.6% राष्ट्रीय आय और 40.1% संपत्ति (औसत आय: 53 लाख रुपये/वर्ष)। शीर्ष 10%: 57% राष्ट्रीय आय (औसत आय: 13 लाख रुपये/वर्ष)। मध्यम 40%: 30% राष्ट्रीय आय (औसत आय: 1.65 लाख रुपये/वर्ष)। निचले 50%: 13% राष्ट्रीय आय, 6% संपत्ति (औसत आय: 71,000 रुपये/वर्ष)। Gini इंडेक्स: 2014 में 0.35-0.40 (आय आधारित), 2024 में 0.41। यह औपनिवेशिक काल (1930s, 20.7% शीर्ष 1% हिस्सेदारी) से बदतर है।

भारत में असमानता ख़तरनाक स्तर तक बढ़ गयी है। अभाव के महासमुद्र में समृद्धि के टापू कितने दिन तक टिकेंगे, कहना मुश्किल है। कॉरपोरेट मुनाफ़े के बावजूद मैन्यूफेक्चरिंग क्षेत्र उम्मीद से काफ़ी पीछे है और युवा बेरोज़गारी दर 29 फ़ीसदी तक पहुँच गयी है।

भारत की अर्थव्यवस्था की चमक को लेकर मोदी सरकार के तमाम दावों को यह तथ्य मुँह चिढ़ाता है कि अस्सी करोड़ लोग पाँच किलो राशन के लिए सरकार पर आश्रित हैं। वहीं ग़रीबी, प्रतिव्यक्ति आय और भुखमरी के मानकों पर भी स्थिति अच्छी नहीं है।

गरीबी: ग्लोबल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (MPI) 2024 में भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है (234 मिलियन लोग, 16.4% आबादी)।

प्रति व्यक्ति आय: नॉमिनल 2,730 (2024, 136वाँ स्थान), PPP पर $8,379 (119वाँ स्थान)।

भुखमरी: ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 में 105वाँ स्थान (127 देशों में), स्कोर 27.3 ('गंभीर' श्रेणी)।

मोदी सरकार के बीते 11 सालों में इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नज़र नहीं आता। हालाँकि कॉरपोरेट मुनाफे में सरकार की नीतियों का बड़ा हाथ है। मोदी सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म (चुनिंदा कंपनियों को फायदा) के आरोप हैं। उदाहरण: टैक्स कट (2019): कॉरपोरेट टैक्स 30% से 22% घटाया, जिससे कंपनियों को अरबों का लाभ।

PLI स्कीम: रू. 1.97 लाख करोड़ की सब्सिडी, जो बड़े कॉरपोरेट्स को ज्यादा मिली।

निजीकरण: एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल का निजीकरण, जहाँ चुनिंदा कंपनियों को प्राथमिकता।

गौतम अडानी ने मोदी राज में ज़बरदस्त तरक्क़ी की है। वाइब्रेंट गुजरात समिट (2003) में अडानी की प्रमुख भूमिका थी। 2014 में मोदी PM बने, अडानी की संपत्ति 230% बढ़ी (26 बिलियन)।

सरकार आर्थिक बदहाली और कॉरपोरेट लूट से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों (जैसे मंदिर-मस्जिद) को बढ़ावा देती है। इसके लिए तमाम जतन किये जाते हैं। ये संयोग नहीं कि बिहार चुनाव के ठीक पहले 'द ताज स्टोरी' जैसी फिल्म, रिलीज़ की जा रही है जो ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा बनवाये गये मोहब्बत की निशानी की जगह उसे तेजोमहालय मंदिर बताती है। सुप्रीम कोर्ट, ASI, यहाँ तक कि मोदी सरकार तक अतीत में ऐसे दावों को ख़ारिज कर चुके हैं लेकिन ताजमहल के नाम पर माहौल में तनाव घोलने की तैयारी की जा रही है। ऐसी न जाने कितनी फ़िल्मों को कॉरपोरेट संसाधन उपलब्ध कराता है। इस तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल जारी रहता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

कुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता
वो शख्स कोई फ़ैसला कर भी नहीं जाता
आँखें हैं कि ख़ाली नहीं रहती हैं लहू से
और ज़ख़्म-ए-जुदाई है कि भर भी नहीं जाता
वो राहत-ए-जाँ है मगर इस दर-बदरी में
ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता
हम दोहरी अज़ीय्यत के गिरफ़्तार मुसाफ़िर
पाँव भी हैं शल शौक़-ए-सफ़र भी नहीं जाता
दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है
और तुझ से बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता
पागल हुए जाते हो 'फ़राज' उस से मिले क्या
इतनी सी ख़ुशी से कोई मर भी नहीं जाता।

- अहमद फ़राज़

पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और शिक्षा सहयोग पर पीएम ने दिया जोर

मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित

नई दिल्ली (एजेंसी)। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस आसियान सम्मेलन की थीम सवावेशिता और सततता है, जो कि जो डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन जैसे साझा प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत इन प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा अपने आसियान सहयोगियों के साथ खड़ा रहा है, चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों या अन्य चुनौतियां। उन्होंने ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में बढ़ती साझेदारी का भी जिक्र किया। मोदी ने 2026 को हरित वर्ष घोषित किया। उन्होंने शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और व्यक्ति से व्यक्ति संबंधों को मजबूत करने के लिए हम काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी हमारी सदी है। यह भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि मिशन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग तैयार करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी के साथ काम करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी

ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की और आसियान की अध्यक्षता संभालने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए भारत-आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 26 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में आसियान देशों के प्रमुखों के साथ-साथ अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहे हैं। कुल दस सदस्य देशों के साथ 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है।

त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की हुई जबरदस्त खरीददारी

मन की बात में पीएम ने किया जिक्र, लोगों को दी बधाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री के रेडियो शो मन की बात के 127वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। पीएम ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं और लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात में जीएसटी बचत उत्सव, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, रन फॉर यूनिटी जैसे विषयों पर बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों के दौरान जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पीएम ने कहा कि देश में त्योहारों का उल्लास है।

7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष, यादगार बनाने की अपील

पीएम मोदी देशवासियों से आह्वान किया कि वे 7 नवंबर को 'वंदे मातरम' के 150वें वर्ष को यादगार बनाएं। उन्होंने कहा कि यह गीत हर भारतीय के दिल में भावनाओं और गर्व का संचार करता है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है। मोदी ने कहा कि आगामी दिनों में देशभर में 'वंदे मातरम' से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिसंबर तक भारत बंद कर देगा रूसी तेल खरीदना

- एशिया दौरे पर आए डोनाल्ड ट्रंप का फिर बड़ा दावा

कुआलालंपुर (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे को एक बार फिर से दोहराया है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने में कटौती शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनका दावा है कि रूस तेल बेचकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। वहीं, उन्होंने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।

डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी आगामी बैठक से पहले आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बातचीत एक पूर्ण समझौते पर पहुंचेगी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का एशिया दौरा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक और कच्चे माल पर प्रतिबंधों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। दोनों देशों पर एक ऐसे समझौते पर पहुंचने का दबाव बढ़ रहा है जिससे चल रहे व्यापार युद्ध को रोका जा सके। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के दौरान चीन द्वारा रूस से तेल खरीद का जिक्र करेंगे, अमेरिकी नेता ने सकारात्मक जवाब दिया। ट्रंप ने दावा किया। मैं भले ही इस पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि चीन, आपने शायद आज देखा होगा - रूसी तेल की खरीद में काफी कटौती कर रहा है, और भारत पूरी तरह से कटौती कर रहा है, और हमने प्रतिबंध भी लगाए हैं।

बहनें अब 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बन रही हैं : मुख्यमंत्री

कृषि-उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण के साथ बायोटेक और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी अब पहचान बना रही हैं महिलाएँ

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बहनें अब 'जॉब सीकर' नहीं, 'जॉब क्रिएटर' बन रही हैं। उद्योग और निवेश के क्षेत्र में महिलाएं वह आत्मविश्वास लेकर आई हैं, जो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का 'ग्रोथ इंजन' बनाएगा। प्रदेश के 47 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी है। लखपति दीदी योजना से प्रदेश की एक लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। आज 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से लगभग 62 लाख बहनें जुड़कर न सिर्फ अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी अपना योगदान दे रही हैं। ग्रामीण अंचलों में स्व-सहायता समूह अब उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। प्रदेश की महिलाएं कृषि-उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, बायोटेक और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भोपाल वुमेन हब

द्वारा आयोजित एमपी एक्सीलेंस अवॉर्ड-2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को समाज की धूरी माना गया है। हम माँ सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि, माँ लक्ष्मी से धन और सम्पदा और माँ दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। हमारे लिए बहन, बेटियां देवी समान हैं। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म महिला सशक्तिकरण का प्रभावी प्लेटफार्म बन चुका है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता की दिशा में सशक्त बनाने में सहायक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा स्वागत स्वरूप कथक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर भोपाल वुमेन हब की गतिविधियों और एमपी एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के उद्देश्यों पर लघु फिल्म की प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ.यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जारी महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, प्रदेश में संचालित विकास गतिविधियों और जनकल्याण कार्यक्रमों पर भी लघु फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम में विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, जिला अध्यक्ष श्री रविन्द्र यति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मान समारोह में श्रेणी-1 में सुश्री गौरांशी शर्मा, सरगम कुशवाहा, भावना देहरिया, सिद्धि मिश्रा, निशिता पाठरकर, शांति देवी, श्रुति अधिकारी, लता मुंशी, मुस्कान रघुवंशी, संगीता राजगीर, शिवि श्रीवास्तव, सोमित दुबे, कनिष्का शर्मा, शिखा शर्मा, मनन सिंह और अविराज सिंह ठाकुर को सम्मानित किया। श्रेणी-2 में नमन देशमुख, मयंक तिवारी, सिमरन बहल, विजय निहाल चंदानी, माही पवार, इशिका ककड़े, देवेंद्र गोरे, चिन्मय गोधा, आयुष गुप्ता, दैविका वघेला, वंशदीप, आरविका गुप्ता और सुषांत कौशल को सम्मानित किया।

जयपुर में विदेशी जोड़ों ने हिंदू रीति और रिवाज से की शादी

- मांग भरी, सात फेरे लिए, दुल्हन की मां ने दूल्हे की नाक खींचकर रस्म निभाई

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर में शनिवार को सामूहिक विवाह समारोह में 30 जोड़ों की शादी हुई। इस सामूहिक विवाह में रूस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईरान से आए 6 जोड़ों ने भी हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की। विदेशी दूल्हों ने भी दुल्हन की मांग भरी और 7 फेरे लिए। शाम करीब 5 बजे गणेश पूजा के बारात रवाना हुई। ढोल-नगाड़ों के साथ बारात निकली बारात में 30 घोड़ियों पर दूल्हे सज-धज कर बैठे। ईरान के रहने वाले दूल्हे अली ने बारात में डांस किया। पांडाल में बारात पहुंचने पर दुल्हन पक्ष की ओर से स्वागत किया गया।

पूरे बंगाल में 500 से अधिक विस्तारकों की होगी नियुक्ति

- विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की बड़ी तैयारी, कसी कमर

कोलकाता (एजेंसी)। भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भाजपा चुनाव को ध्यान में रखकर राज्य में 500 से अधिक विस्तारकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसमें अब तक 250 पुरुष विस्तारकों को बहाल किया जा चुका है, जिन्हें 250 विधानसभा सीटों पर तैनात किया जाएगा। इन विस्तारकों की ट्रेनिंग इसी सप्ताह कोलकाता में होगी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 30°c
न्यूनतम 25°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ सोमवार, 27 अक्टूबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पुस्तकीय ज्ञान के साथ समसामयिक जानकारी जरूरी : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल 'मन की बात' कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण आयोजन में हुए शामिल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही देश में हो रही प्रगति और विकास के बारे में समसामयिक जानकारी होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम ऐसी अद्भुत पहल है, जिसमें देश में हो रहे नवाचारों और प्रगति की जानकारी मिलती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में मन की बात कार्यक्रम के सामूहिक श्रवण की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है।

राज्यपाल श्री पटेल रविवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में मन की बात के सामूहिक श्रवण कार्यक्रम के छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। सामूहिक श्रवण कार्यक्रम का आयोजन ज्ञान विज्ञान भवन में किया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय आगमन पर ज्ञान विज्ञान भवन परिसर में पौधरोपण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विश्वविद्यालय की छात्राओं जैनस्वी शर्मा, खुशी सेन ने हम उठे जग उठे, लक्ष्य गीत का गायन किया।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम राष्ट्र जागरण की अभूतपूर्व पहल है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब, वंचित और पिछड़े व्यक्तियों और क्षेत्रों के द्वारा देश-समाज के निर्माण में दिये जा रहे योगदान की जानकारी दी जाती है। इन प्रेरक प्रसंगों से आत्मबल से विकास और परिवर्तन के लिए समाज को आत्मविश्वास, प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होती है। इसी तरह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री ने विद्यार्थी परीक्षा की कैसे तैयारी करें, पालक बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इन सभी विषयों पर विस्तार से समझाइश देकर छात्र-छात्राओं पर अनावश्यक रूप से परीक्षा के समय बनने वाले भारी दबाव कम करने में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकसित भारत@2047 की नई पहल की है। आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा इस दिशा में विवेकानंद जयंती के अवसर पर नई पहल की है। देश भर के विद्यार्थियों से राष्ट्र के भावी स्वरूप के संबंध में उनके विचार प्राप्त किये। चयनित 3 हजार युवाओं के साथ नई दिल्ली में गोष्ठी भी की है।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि ज्ञान के साथ संस्कार से ही जीवन अच्छा जीवन होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार देना केवल शिक्षण संस्थाओं का दायित्व नहीं हो सकता। परिवार को भी बच्चों में संस्कार देने की जिम्मेदारी समझना होगी। बच्चे माता-पिता के आचरण से संस्कार ग्रहण करते हैं। परिवार का वातावरण संस्कारित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से प्राप्त प्रगति अधूरी है। यदि उसमें अपने माता-पिता, राष्ट्र, समाज के प्रति सम्मान और सेवा का भाव नहीं है। उन्होंने कहा माता-पिता अपने बच्चों की अंगुली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। वृद्धावस्था में उनके साथ दुर्व्यवहार करके कोई भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कुलगुरू श्री एस.के. जैन ने स्वागत उद्बोधन दिया। आभार प्रदर्शन कुल सचिव डॉ. अनिल शर्मा ने किया। संचालन अधिष्ठाता छात्र कल्याण श्री पवन मिश्रा ने किया।

रीवा स्पेशल सुपरफास्ट की रफ्तार पर सवाल

समान ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन समय पर, हफ्ते में 1 दिन चलने वाली सुपरफास्ट 10 घंटे लेट

भोपाल (नप्र)। रानी कमलापति स्टेशन से रीवा के बीच चलने वाली दो ट्रेनों की रफ्तार में जमीन-आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है।

रोजाना रात 10 बजे चलने वाली ट्रेन नंबर 12185 रेवांचल एक्सप्रेस अपने तय समय यानी अगले दिन सुबह 8 बजे रीवा पहुंच जाती है। कई बार तो यह 10 से 15 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। वहीं इसके सिर्फ 15 मिनट बाद यानी रात 10:15 बजे चलने वाली ट्रेन नंबर 02191 रीवा स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अक्सर घंटों की देरी से पहुंच रही है। इस ट्रेन का शेड्यूल समय हर शनिवार रात 10:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होने का है और अगले दिन सुबह 7:20 बजे रीवा पहुंचने का तय समय है। लेकिन पिछले एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि यह ट्रेन कई बार 10 से 12 घंटे तक की देरी से रीवा पहुंची है। डब्ल्यूसीआर के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव ने बताया हम ट्रेनों के समय पालन का पूरा ध्यान रखते हैं। कई बार ऑपरेशनल इश्यूज के चलते ऐसा होने की संभावना बनती है। हमारी पूरी कोशिश है कि सभी स्पेशल ट्रेन समय पर चलें।

15 मिनट पहले चलने वाली ट्रेन समय पर, फिर भी सुपरफास्ट क्यों स्लो?– इसी रूट पर रोजाना चलने वाली ट्रेन नंबर 12185 रेवांचल एक्सप्रेस रात 10 बजे रानी कमलापति से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 8 बजे रीवा पहुंच जाती है। यह ट्रेन अधिकतर दिन समय पर या 10-15 मिनट पहले रीवा पहुंचती है।

हमने रेवांचल एक्सप्रेस का जिक्र सिर्फ तुलना के लिए किया है, ताकि यह समझा जा सके कि जब समान रूट और दूरी में रोजाना चलने वाली ट्रेन समय पर पहुंच रही है, तो सप्ताह में एक बार चलने वाली 'सुपरफास्ट' एक्सप्रेस इतनी देरी से क्यों?

रेवांचल के ज्यादा स्टॉप, फिर भी समय पर– रेवांचल एक्सप्रेस के भोपाल, विदिशा, गंज बासौदा, मंडी बामोरा, बीना, खुरई, सागर, पथरिया, दमोह, कटनी मुड़वारा, अमदरा, मैहर, उंचेहरा, सतना और रीवा में स्टॉप हैं। वहीं, रीवा स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के स्टॉप इससे कम हैं, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, मैहर, सतना और रीवा। कम ठहराव होने के बावजूद रीवा स्पेशल लगातार लेट होना यात्रियों और विशेषज्ञों दोनों को चौंका रहा है। पिछले 4 शेड्यूल में औसतन 9 से 12 घंटे की देरी 18 अक्टूबर– शेड्यूल ट्रेन अगले दिन 10 घंटे 48 मिनट की देरी से रीवा पहुंची।

11 अक्टूबर– ट्रेन 10 घंटे 27 मिनट देरी से पहुंची।

4 अक्टूबर– ट्रेन 12 घंटे 48 मिनट देरी से पहुंची।

27 सितंबर– ट्रेन 4 घंटे 37 मिनट लेट रही। यानी 'सुपरफास्ट' नाम के बावजूद ट्रेन की औसत देरी 9 से 10 घंटे के बीच रही।

मलबे में दब गए दुकानदारों के सैकड़ों सपने, लगाते रहे गुहार

मेरठ (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को शहर के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में बने 35 साल पुराने तीन मंजिला कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें थीं, जो स्थानीय व्यापारियों की आजीविका का जरिया थीं। जैसे ही बुलडोजर चला, वहां मौजूद व्यापारी और उनके परिवार फफक पड़े। किसी के लिए वह दुकान रोज़ी-रोटी का सहारा थी, तो किसी के लिए पीढ़ियों की मेहनत की पहचान। शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्रवाई करीब सात घंटे चली। पहले दिन

कॉम्प्लेक्स का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा गिराया गया। रविवार को सुबह साढ़े 9 बजे फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी तैनात रही। ड्रोन से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही थी। कॉम्प्लेक्स के गिरते ही आसपास धूल का गुबार छा गया। अलंकार साड़ी सूट्स शॉप के मालिक विनोद अरोड़ा अपनी पत्नी, बहन और बेटों के साथ सुबह से ही कुर्सी पर बैठे अपनी दुकान को निहारते रहे। जैसे ही बुलडोजर ने दीवारें तोड़ीं, परिवार की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कहते हैं इस दुकान से ही घर चलता था, अब कैसे गुजारा करेंगे। आसपास के अन्य दुकानदार भी अपने टूटे सपनों को देखकर मायूस खड़े रहे। कई महिलाओं ने अधिकारियों से हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे किसी की एक न चली। यह कॉम्प्लेक्स करीब 288 वर्गमीटर भूमि पर बना था।

आंध्र-बंगाल में तबाही मचाने आ रहा चक्रवाती तूफान

तूफान 'मोंथा' का बढ़ा खतरा, हाई अलर्ट पर आर्मी

ओडिशा के सभी 30 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी मध्य अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम के मद्देनजर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगले 48 घंटों में चक्रवात मोंथा के रूप में तीव्र होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती तूफान की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा धीरे-धीरे पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी 30 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में तूफान का असर देखने को मिलेगा। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही सावधानी बरतते हुए राहत और आवश्यक आपूर्ति के लिए रणनीति तैयार कर ली है। एनडीआरएफ और सेना की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मोंथा के आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के नजदीक 28 अक्टूबर की शाम या देर रात के समय टकराने की संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द

इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। विभाग ने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 28 और 29 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश होगी। ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण होने वाली तबाही से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने निचले इलाकों से लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों के 15 जिलों के चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम दोनों जिलों के अधिकारी चक्रवात 'मोंथा' के तूफानी प्रभाव से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए तैयार हैं।

दलित युवक के मर्डर केस में 2 और आरोपी अरेस्ट

- सरकारी नौकरी की मांग, सपा-कांग्रेस ने सरकार को घेरा

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)। रबूपुरा में पिछले दिनों पिटाई से दलित युवक की मौत मामले में विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहली गिरफ्तारी रबूपुरा निवासी रचित की हुई। वह यमुना एक्सप्रेसवे से फरार होने की फिराक में था। दूसरे आरोपी अंकित को यमुना सिटी के सेक्टर-18 से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले युवराज मीणा और जीतू मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, पुलिस ने सपा के एक नेता को गांव जाने से रोक दिया और भड़काऊ भाषण पर टोका, जिस पर उन्होंने माफी मांगी।

पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर का विदेशी कनेक्शन

दुबई में 2, कनाडा में 3 फ्लैट, 20 दुकानों का भी पता चला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। रिश्वत केस में पकड़े पंजाब के रोपड़ रेंज के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। भुल्लर के ड्यूटी के दौरान ही करीबन 10 बार दुबई यात्रा पर जाने की चर्चा है। सीबीआई ने भुल्लर का पासपोर्ट अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसके माध्यम से उनके विदेश दौरों की डिटेल जुटाई जा रही है। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों अनुसार अब तक भुल्लर के दुबई में 2 और कनाडा में 3 फ्लैट का पता चला है। इसके अलावा उनके पास लुधियाना में लगभग 55 एकड़ जमीन और माछीवाड़ा क्षेत्र में 20 दुकानों की जानकारी भी सीबीआई के हाथ लगी है। सीबीआई को शक है कि भुल्लर ने अपनी तैनाती के दौरान विदेशों में भी संपत्ति बनाई। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एजेंसी अब इन सभी संपत्तियों के सोर्स का पता लगाने में जुटी है और यह जांच भी की जा रही है कि क्या इन संपत्तियों को किसी अन्य नाम पर खरीदा गया था। आने वाले दिनों में भुल्लर की संपत्तियों को लेकर और खुलासे होने की संभावना है। पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि इस तरह के अधिकारियों के बारे में मंत्रियों और अधिकारियों को पता रहता है।

कृष्णु को सरकारी गवाह बना सकती है सीबीआई

मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी से रिश्वत की सेटिंग करवाने वाले कृष्णु को सीबीआई की तरफ से सरकारी गवाह बनाया जा सकता है। इसके लिए सीबीआई की तरफ से कृष्णु को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर वह सरकारी गवाह बनता है तो इससे भुल्लर की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।

नालायक को नायक बताना 'नायक' शब्द का अपमान

- पोस्टर पर भड़के जीतन राम मांझी, तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर साधा निशाना

पटना (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। मांझी ने तेजस्वी को नायक बताए जाने पर आपत्ति जताई और इसे नायक शब्द का अपमान करार दिया। मांझी ने पोस्ट में लिखा कि नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पटना स्थित केंद्रीय कार्यालय के बाहर शनिवार को एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पार्टी के नेता तेजस्वी यादव को बिहार का नायक के रूप में बताया गया है। यह पोस्टर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के ठीक बाद लगाया गया है।

हीरा नगर क्षेत्र में मोहल्ला मार्च और बैठक

इंदौर। आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने, शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना हीरानगर क्षेत्र में मोहल्ला मार्च और मोहल्ला मीटिंग का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का नेतृत्व पुलिस उपायुक्त जोन-3 राजेश व्यास ने किया। थाना हीरानगर से शुरू हुआ पैदल मार्च आमवाला चौराहा, खातीपुरा मेन रोड होते हुए गौरीनगर जाम का बगीचा तक पहुंचा। वहां स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को अपराध से दूर रहने और अपने बच्चों को भी अपराध की प्रवृत्तियों से बचाने की समझाइश दी गई। इसके साथ ही मोहल्ले के लोगों से उनकी समस्याएं पर्चियों के माध्यम से बंद डिब्बे में ली गई, ताकि उनका उचित निराकरण किया जा सके। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक समस्या पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और जन-जन की सुरक्षा, पुलिस आपके द्वार की भावना को साकार करना है।

सड़क पर पार्किंग शहर में सबसे बड़ी समस्या, इससे अधिकारी भी परेशान

सारे प्रयास विफल, मैकेनाइज्ड पार्किंग कॉन्सेप्ट भी सफल नहीं हुआ

इंदौर। स्वच्छता में शहर लगातार नंबर-1 रहा है और यह खिताब लगातार 8 बार से बरकरार है, लेकिन यहां की यातायात समस्या किसी से छुपी नहीं है। यातायात में नंबर 1 बनने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। शहर की सबसे प्रमुख समस्या है सड़क पर होने वाली अवैध पार्किंग, जिसका पुलिस और प्रशासन निजात नहीं दिला पाए।

हालात यह है कि भीड़ वाले बाजारों में सड़क पर पार्किंग हो रही है। संभाग आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा और निगम आयुक्त दिलीप यादव के सामने भी इंदौर को यातायात में नंबर 1 बनाना और सड़कों पर होने वाली पार्किंग को रोकना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। शहर में यातायात की समस्या का निराकरण लाखों प्रयासों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा। जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस इस समस्या के निराकरण में जुटी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिल रही। तीनों विभाग सड़कों पर होने वाली पार्किंग को रोकने में असमर्थ हैं। वहीं नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा मैकेनाइज्ड पार्किंग का कॉन्सेप्ट भी सफल नहीं हो सका।

13 मल्टी लेवल पार्किंग में 7 खाली– नगर निगम और यातायात विभाग के सूत्र बताते हैं शहर में 13 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, जिसमें से केवल 6 पार्किंग में वाहन खड़े किए जाते हैं। नगर निगम को इनका मेंटेनेंस करना भी महंगा पड़ रहा है। कृष्णपुरा पुल के पास मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाई गई है जहां पैसा देकर वाहन रखने में लोगों की रुचि नहीं है। पार्किंग का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया गया था, जिसके चलते ठेकेदार को पार्किंग पर विज्ञापन लगाने के अधिकार दिए गए। इससे वह पार्किंग का मेंटेनेंस एवं रखरखाव का खर्च ठेकेदार उठा रहा है, वहीं जो वाहन पार्किंग में रखे जाते हैं उनसे अवैध रूप से वसूली कर ली जाती है।

सारे अभियान फेल हो गए

ट्रैफिक समस्या का निराकरण नहीं होने के पीछे सड़कों पर पार्किंग करना है। शहरवासी यह चाहते हैं कि पार्किंग तक वाहन नहीं ले जाना पड़े। भरे बाजारों में सड़क पर पार्किंग की जाए या फिर वाहन का प्रवेश बाजारों में भी हो ताकि चार पहिया वाहन में ही खरीदी भी की जा सके। 10 सालों से देखने में आया है कि सड़कों पर होने वाली पार्किंग को कम करने अनेक अभियान चलाए गए। मल्टी लेवल पार्किंग के साथ मैकेनाइज्ड पार्किंग भी बनाई, लेकिन यह पार्किंग बेकार पड़ी हुई है। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त आनंद कलादगी के मुताबिक, सड़क पर वाहन पार्क करने वालों को लेकर जल्द ही बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम में वाहन जब्ती के साथ उनके चालान भी काटे जाएंगे।

परिक्रमा

हेमंत के सामने भाजपाइयों को साधने की चुनौती

अरुण पटेल

लेखक सुबह सवेरे के प्रबंध संपादक हैं

मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और महामंत्री संगठन हितानंद शर्मा की पसंद को तरजीह देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जो अपनी 29 सदस्यीय टीम गठित की है उसमें 16 नये चेहरे हैं जबकि 13 पुराने चेहरों को तरजीह दी गयी है जिसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। अब हेमंत खंडेलवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लिए जा रहे निर्णयों और जनहितैषी कार्यों को मैदानी स्तर तक पहुंचाने और उसे जनमानस के दिलोदिमाग में बिठाने की चुनौती होगी ताकि भाजपा का बढ़ा हुआ जनाधार और अधिक व्यापक हो सके। जहां तक नेताओं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पसंदीदा व्यक्तियों को सवाल है उन्हें भी नई टीम में जगह मिल गयी है। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को पुन: वही दायित्व सौंपा गया है जो उन्होंने अभी तक बड़ी कुशलता व दक्षता से निभाया है। जिन लोगों की छुट्टी की गयी है वह किसी न किसी कारण या तो सुर्खियों में रहे या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जो संगठन को रास नहीं आया।

पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद जैसा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में होता आया है, नये पदाधिकारियों को नसीहत व उपदेशों की घुट्टी पिलाई गई है। इसका कितना असर हुआ यह तो नये पदाधिकारियों की कार्यशैली के सामने आने के बाद पता चलेगा। किसी भी पार्टी की छवि जनमानस में उसके पदाधिकारियों के कार्य-व्यवहार एवं आचार-व्यवहार से बनती है और इसी से बिगड़ती भी है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि 'प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो- टेढ़ो जाए', इससे यदि नये पदाधिकारी बच सके तो फिर इसका अच्छा-खासा प्रभाव देखने में नजर आ सकता है। क्योंकि आम जनमानस तो इसे ही पार्टी का आचरण-व्यवहार मानती आई है। यही कारण है कि पदाधिकारियों को यह नसीहत दी गयी कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे पार्टी की छवि व कार्यकर्ताओं के मन पर विपरीत असर पड़ता हो। नये पदाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि वे जमीन से जुड़कर रहें, यानी कार्यकर्ताओं के बीच रहें और सबको साथ लेकर चलें। नसीहत की यह घुट्टी भाजपा के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने वर्चुअली पिलाई।

नये पदाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलहाल बिहार चुनाव में प्रदेश के नेता व्यस्त हैं इसलिए बैठक आयोजित नहीं हो रही है और पहली बैठक बिहार चुनाव के बाद होगी। लेकिन सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार अभी से काम में जुट जायें। भाजपा के आगामी कार्यक्रम को लेकर भी नयी टीम को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। फिलहाल तो नये पदाधिकारियों से यही अपेक्षा की गयी है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ें, अपनी सहभागिता बढ़ायें और आगामी 31 अक्टूबर को लौह पुरुष और भारत के पहले उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सक्रिय रहें। भाजपा का समूचा ध्यान इस समय आदिवासी समाज के बीच अपनी पैठ बढ़ाना और उन्हें पार्टी से जोड़ने का है और इसीलिए 15 नवम्बर को भाजपा की ओर से बिरसा मुंडा जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जायेगा। ऐसे में पार्टी प्रदेश के सभी आदिवासी जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ायेगी और इसमें नये पदाधिकारियों से भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की अपेक्षा की गयी है।

और यह भी

नीति आयोग के सहयोग से मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा विकसित मध्यप्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया जा रहा है उसका विमोचन मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर को होगा। इसी दिन डॉ. यादव की उपस्थिति में इनवेस्ट एमपी और एमपी ई-सेवा पोर्टल भी लांच किया जायेगा। इसके साथ ही तीन दिवसीय कार्यक्रम भी होंगे जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। इन आयोजनों के लिए सरकार हर जिले को व्यवस्था के लिए एक-एक लाख रुपये दे रही है। बाकी व्यवस्था कलेक्टर अपने स्तर पर करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग जो निर्देश दिये गये हैं उनमें जिला स्तरीय कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला मुख्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिलावार उत्कृष्ट कार्यों से सम्बद्ध गौरव चरित्रों पर केंद्रित जिला उत्पादों का प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जायेगी और सभी कार्यक्रमों से संबंधित तैयारियों की जानकारी से जिले के प्रभारी मंत्री को अवगत करायेंगे एवं उनके परामर्श से कार्यक्रम को अंतिम रुप देंगे।

निगम और भाजपा पार्षद विवाद में नया मोड़

महिलाओं से बदसलूकी का भी मामला दर्ज

देर रात तक थाने में हंगामा, तीन और महिलाओं ने ऐसी ही शिकायत की

इंदौर। नगर निगम अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बीच हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। संपत्ति कर सर्वे जांच को लेकर निगम अफसर और भाजपा पार्षद के बीच हुए विवाद के बाद कई पार्षद भंवरकुंआ थाने पहुंचे। इसके बाद रात 3 बजे तक हंगामा। हुआ दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। रविवार को निगम के अधिकारियों के खिलाफ एक महिला ने बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई। तीन अन्य महिलाओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए।

यह पूरा विवाद नगर निगम के जोनल कार्यालय क्रमांक 13 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 74 में शुरू हुआ, जहां निगम की टीम घर-घर जाकर संपत्ति कर चोरी पकड़ने के लिए नपती अभियान चला रही है। इस जांच में निगम के कर्मचारियों ने पाया कि कई जगहों पर नागरिकों ने खुला प्लॉट बताकर टैक्स दिया, जबकि वहां पर बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर निर्मित क्षेत्र कम दिखाकर भी संपत्ति कर की चोरी की जा रही थी। इस दौरान निगम की टीम और क्षेत्रीय पार्षद सुनील हार्डिया समेत भाजपा नेताओं के बीच तीखा विवाद हो गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि कुछ मकानों की जांच रोकने का दबाव डाला जा रहा, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस थाना भंवरकुआं में दो एफआईआर दर्ज की गई। एक नगर निगम अधिकारियों की ओर से पार्षद और उनके भाइयों पर। दूसरी एक नागरिक द्वारा निगम अधिकारी एआरओ शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ।

रात को थाने पर भारी गहमा-गहमी और हंगामा का माहौल बन गया। भाजपा के सात पार्षद अपने समर्थकों के साथ थाने में डेरा डालकर बैठ गए और निगम अधिकारियों के खिलाफ और केस दर्ज करवाने का दबाव बनाने लगे। इसी दौरान एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ महिला से बदसलूकी का मामला दर्ज कर लिया। डीसीपी आनंद कलादगी ने पुष्टि करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही तीन और महिलाओं ने भी अपने घरों में घुसकर निगम कर्मचारियों द्वारा गलत व्यवहार करने की शिकायत की हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच में लिया। थाने पर रात करीब 3 बजे तक भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही। निगम और भाजपा के बीच यह टकराव अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान और सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

कांग्रेस नेताओं के बयान

इस मामले पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कमेंट किया 'बीजेपी की साफ-सुथरी राजनीति का सच इंदौर में दिखाई दे रहा!' यहां नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की टीम में जमकर ठनी हुई है! निगम कमिश्नर ने बीजेपी पार्षदों को भी हाशिए पर रख दिया। वे उनकी भी नहीं सुन रहे।

सम्पत्ति कर की जांच के लिए निगम के अफसरों ने जबरन लोगों के घर में घुसकर नाप-जोख करना शुरू कर दिया, जिसे लेकर पार्षदों ने विरोध किया, विवाद के बाद मारपीट हुई। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। यानी एक तरफ निगम कमिश्नर और अफसर दूसरी तरफ महापौर और बीजेपी पार्षद। ये पहली बार हुआ, जब नगर निगम प्रशासन और बीजेपी पार्षदों में जंग छिड़ गई। जिस शहर के प्रभारी मंत्री खुद सीएम हों, वहां ऐसी घटनाएं तात्कालिक नहीं होती। इनके पीछे कई समीकरण जुड़े होते हैं, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। बस जानने और समझने की जरूरत है!

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी 'एक्स' पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा श्री दिलीप यादव जब से इंदौर में नगर निगम आयुक्त बने हैं, बीजेपी पार्षद ही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं! कमीशन/करप्शन के लिए बदनाम यह 'नरक निगम' यदि 'वसूली' के लिए नागरिकों को प्रताड़ित करेगा, तो विरोध जायज है! भाजपा पार्षद की पीड़ा जरूर सुनें!

भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने का अभियान पकड़े भिक्षुकों को उज्जैन आश्रम भेजेंगे

इंदौर। शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए शनिवार को कार्रवाई की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर चल रही इस कार्रवाई में भिक्षा लेने और देने वाले दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं उनकी टीम ने शनिवार को एमवाय हॉस्पिटल के सामने लगातार बैठ रहे भिक्षुकों पर कार्रवाई की। भाजपा कार्यालय के सामने स्थित गार्डन एवं दुकानों के समक्ष कई दिनों से रह रहे भिक्षुकों को भी पकड़ा गया।

इसके पहले यह मुहिम पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह ने चलाई थी। उस मुहिम का सख्ती से पालन होने पर कहीं भी भिक्षुक नजर नहीं आते थे। भिक्षुकों को रेस्क्यू कर पल्सीकर कॉलोनी स्थित रेन बसेरा में शिफ्ट किया गया। एमवाय हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ, बस स्टॉप पर किए गए कब्जे को भी इनसे खाली करवाया गया। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि इन्हें 15 दिनों के लिए उज्जैन शेल्टर हाउस सेवा धाम, भेजा जाएगा। जहां पर उनकी काउंसलिंग एवं संभव सहायता की जाएगी। उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा।

इसके पूर्व नगर निगम चौराहा से लेकर एमजी थाने तक की पट्टी पर एमजी थाना प्रभारी, नगर निगम एवं महिला बाल विकास की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। महिला बाल विकास एवं अन्य विभागों के समन्वय से बनी टीमों के द्वारा लगातार नगर के सभी मंदिर, मस्जिद, चौराहों आदि की निगरानी की जा रही है बताया जा रहा है कि रेस्क्यू करने के दौरान एमवाय अस्पताल में मरीजों के साथ आए परिजन को वर्ल्ड कप चौराहा रैन बसेरा में रुकने का इंतजाम किया गया।

पकड़ी गई थी लखपति भिखारन - पिछले साल फरवरी में जब इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान चला था, तो एक ऐसी महिला भिखारी पकड़ में आई, जो अपने दोनों बच्चों समेत भीख मांगने का काम करती थी। वह उज्जैन रोड पर लवकुश चौराहे पर भीख मांगती थी। उसका कहना था कि उसने पौने दो महीने में चौराहे पर भीख मांगकर ढाई लाख रुपए कमाए और एक लाख रुपए उसने अपने सास-ससुर को भेजे। पूछताछ में महिला ने अपने पास कई संपत्ति होने का भी खुलासा किया था। उसने बताया था कि उसके पास एक जमीन, दो मंजिला घर, एक बाइक, 20 हजार रुपए का स्मार्टफोन भी है। इस महिला ने भी अपना घर राजस्थान में होना बताया था।

दीपावली मिलन और अन्नकूट महोत्सव

इंदौर। श्री राजस्थान कुमावत क्षत्रिय समाज द्वारा इस वर्ष में बालाजी महाराज की असीम कृपा से दीपावली मिलन समारोह और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर को राजशाही रिसोर्ट बिचोली मर्दाना पर किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष बाबूलाल भरेदिया ने बताया कि इसमें राजस्थानी लोक गायक संजय मुकुंदगढ़ भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के तहत सुबह 11.15 से 12 बजे तक दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण, दोपहर 12 से 2 बजे तक भोजन, 2 से शाम 5.45 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस स्पर्धा एवं समाज सेवकों का स्वागत, 5.45 से 6.15 बजे तक पुरस्कार वितरण और होनहार बच्चों का सम्मान, 6.15 से 6.30 बजे तक भजन मंडली में आने वाले गोदान का लेखा जोखा रखा गया।

दो पहिया वाहन चालकों की चैकिंग बॉडी वार्न कैमरे, पीओएस मशीन से

इंदौर। ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन चालकों को नियम अनुसार चलने की समझाइश दे रही है। इसके लिए स्कूलों, प्रतिष्ठानों, चौराहों पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, लेकिन वाहन चालक मानने को तैयार नहीं।

पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आगामी 6 नवंबर से कड़ा एक्शन लेने जा रही है। वाहन चालकों पर कार्रवाई के दौरान वे बॉडी वार्न कैमरे से लैस रहेगी और पीओएस मशीन से ही राशि जमा कराएगी। कैमरों में रिकॉर्डिंग की सतत मॉनिटरिंग भी होगी। यातायात डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि इस सप्ताह से हेलमेट जागरूकता और यातायात नियमों के पालन को लेकर 15 दिन का विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। 5 नवंबर तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान के बाद 6 नवंबर से नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी।सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह अभियान शुरू किया है। 5 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान सीएसआर एक्टिविटी के जरिए मुफ्त हेलमेट वितरण भी किया जा सकता है। चेकिंग के दौरान पॉइंट पर पर्याप्त स्टॉपर रखे जाएंगे, नियमित रूप से नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस अमान्य करने के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजे जाएंगे, यदि चेकिंग के दौरान कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाले वाहन चालक को बिना कार्रवाई के छोड़ता है तो इसके लिए पुलिसकर्मी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तथा हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट गूगल शीट के जरिए पीटीआरआई को भेजनी होगी।आमतौर पर चालानी कार्रवाई के दौरान वाहन चालक और पुलिस जवान में विवाद होता है। विवाद के दौरान कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि पुलिसकर्मी ने चालक से अभद्रता की, उससे पैसे लिए हैं। बाडी वार्न कैमरे से इस तरह के विवादों का स्थायी निपटारा हो जाएगा।

- **नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन में आएगी ट्रैफिक पुलिस**

ट्रैफिक प्रहरी अभियान का शुभारंभ यातायात के लिए पुलिस की पहल

इंदौर। सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में आमजन की सहभागिता बढ़ाने पुलिस ने ट्रैफिक प्रहरी अभियान की शुरूआत की है। अभियान में पुलिस उपायुक्त जोन-4 आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संतोष कौल, सहायक पुलिस आयुक्त मनोज खत्री, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सभी ने इस पहल का स्वागत कर सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। डीसीपी ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत कर बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यातायात प्रबंधन और नियम पालन में सहभागी बनाना है, ताकि शहर में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वे क्यूआर कोड स्कैन कर गूगल फॉर्म के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। इच्छुक नागरिक अपनी सुविधा अनुसार समय और स्थान का चयन कर यातायात प्रहरी के रूप में कार्य कर सकेंगे।

अभियान से जुड़ने वाले स्वयंसेवकों को यातायात पुलिस की ओर से सिटी, लाइट बेटन, जैकेट और बैज प्रदान किए जाएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक प्रहरियों को साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाएगा। चौराहों और त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने में, नियम उल्लंघन की सूचना देने में, दुर्घटना या ट्रैफिक जाम की जानकारी साझा करने में और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने में आमजन ट्रैफिक पुलिस की मदद कर सकेंगे।

मेट्रो ट्रेन को लेकर कई जगह स्थिति स्पष्ट नहीं, विजय नगर से आगे का काम रुका

मेट्रो स्टेशन छोटा गणपति पर बनाने की तैयारी को देखकर विवाद बढ़ा

इंदौर। मेट्रो को सुपर कॉरिडोर से विजयनगर तक ट्रैक पर लाकर इसे शहर में आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर रोबोट चौराहे से रीगल के बीच ट्रैक का काम अंडरग्राउंड करने को लेकर उलझ गया। छोटा गणपति मेट्रो स्टेशन की तैयारी का विरोध। लोगों का कहना है कि ट्रैक सुभाष मार्ग पर शिफ्ट कर रहे, तो यहां निर्माण कैसे!

मेट्रो ट्रेन का काम अलग-अलग फेज में चल रहा है। वर्तमान में गांधी नगर से रोबोट तक का काम हो गया। इसके आगे का मामला उलझ गया है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रोबोट से एयरपोर्ट के बीच एलिवेटेड व अंडरग्राउंड ट्रैक का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन मामला अंडरग्राउंड रैंप बनाने और दो स्टेशन को लेकर उलझा हुआ है। अंडरग्राउंड ट्रैक निर्माण कंपनी ने छोटा गणपति स्टेशन, मल्हारगंज पर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कंपनी ने ऑफिस के लिए बगीचे में कंटेनर रख दिया। जब रहवासियों ने इसकी वजह पूछी तो वे बोले हमारे पास अलाइनमेंट यही है। स्टेशन यहीं बनेगा। जवाब सुनकर रहवासी भड़क गए। वे महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पास पहुंचे। अभी भी यह मामला सुलझा नहीं है। वर्तमान में अंडरग्राउंड रैंप एमजी रोड पर हाई कोर्ट के सामने बन रहा है। लोग व जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है, इसे खजराना से बंगाली के बीच अंडरग्राउंड किया जाए। सारा मामला राशि को लेकर अटका हुआ है। ट्रैक में बदलाव करने पर लागत में करीब 1000 करोड़ का अंतर आएगा। यह राशि राज्य सरकार को देना होगी। अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। बैंक से राशि भी मंजूर हो गई है। इसे कम करने के लिए पत्रकार कॉलोनी या छोटा गणपति स्टेशन को हटाने पर विचार चल रहा है, जिससे राशि में कमी आ जाए। वहीं, जगह में बदलाव करने पर दोनों कंपनियों की टेंडर शर्तों में फेरबदल होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड ट्रैक में किलोमीटर बढ़ेंगे, वहीं एलिवेटेड में कम होंगे।रहवासियों ने बताया, जब सुभाष मार्ग पर पुलिस लाइन की सरकारी जगह पर शिफ्ट करने का निर्णय हो गया, जगह का सीमांकन कर लिया गया फिर कंपनी यहां काम कैसे शुरू कर रही है। महापौर ने कहा, एक-दो दिन में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसमें दोनों स्टेशन पत्रकार कॉलोनी व छोटा गणपति के विकल्प देखकर निर्णय लेंगे। मेट्रो अफसरों का कहना है, स्टेशन का एलाइनमेंट बदलने में परेशानी होगी।

संपादकीय

केरल की बड़ी कामयाबी

केरल राज्य की इस उपलब्धि को राजनीतिक दुराग्रहों से हटकर समग्र देशहित के चश्मे से देखा जाना चाहिए। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अत्यंत गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह उपलब्धि केरल मॉडल की ताकत को दर्शाती है, जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। केरल में वामपंथी मोर्चे की सरकार है। गौरतलब है कि यह राज्य 1 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में अत्यंत गरीबी-मुक्त राज्य की घोषणा करेगा। नीति आयोग ने इसकी पुष्टि की है कि केरल ने चरम गरीबी ($2.15 प्रति दिन से कम, लगभग रू. 180) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह उपलब्धि विश्व स्तर पर चीन के बाद दूसरी है। नीति आयोग के 2021 के आंकड़ों में केरल की गरीबी दर पहले ही 0.7% थी - देश में सबसे कम। इसके बाद विजयन सरकार ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत 64,006 परिवारों को अत्यंत गरीब के रूप में चिन्हित किया गया। प्रत्येक परिवार के लिए व्यक्तिगत योजनाएँ बनाई गईं - भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका, और आवास पर ध्यान। 21,263 लोगों को राशन कार्ड, आधार, वोटर ID जैसे दस्तावेज दिए गए। 3,913 परिवारों को घर, 1,338 को भूमि, और 5,651 घरों की मरम्मत के लिए रू. 2 लाख तक की सहायता। यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं थी। केरल में वामपंथी (LDF) और कांग्रेस-नेतृत्व वाली (UDF) सरकारों ने दशकों से शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को प्राथमिकता दी। स्थानीय निकायों (पंचायत, नगरपालिका) और कुडुंबश्री जैसे महिला सशक्तिकरण मिशनों ने एकजुट होकर इसे संभव बनाया। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 75 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी ($3 प्रति दिन से कम) में जी रहे हैं। लेकिन इस बीच, केरल ने चमत्कार कर दिखाया है - केरलः अत्यंत गरीबी का खात्मा। साथ ही जियो-टैगिंग से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। दरअसल केरल मॉडल की ताकत इसके इंसान-केंद्रित विकास में है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, केरल 79 अंकों के साथ मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत का शीर्ष राज्य है। जबकि 57 अंक लेकर बिहार सबसे निचले स्थान पर है। जिन मानकों के आधार पर केरल ने यह उपलब्धि हासिल की है, वो हैं- साक्षरता दरः केरल की 96.2% (राष्ट्रीयः 77.7%, वैश्विकः 86.5%) - विश्व औसत से 10% अधिक। जीवन प्रत्याशाः 78.26 वर्ष (भारतः 72, विश्वः 73.1) - यूपी/बिहार से 8 वर्ष ज्यादा। स्वास्थ्यः प्रति व्यक्ति रू. 1,000 स्वास्थ्य पर खर्च (राष्ट्रीयः रू. 250 से कम)। प्रति 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर (WHO मानक)। शिशु मृत्यु दरः 5 प्रति 1,000 (भारतः 25, अमेरिकाः 5.6)। शिक्षा बजटः GDP का 3.46% (भारतः 1.9% से कम)। मजदूरीः औसत रू. 700/दिन (राष्ट्रीय औसत का 4 गुना, मध्य प्रदेशः रू. 292)। इसके अलावा केरल का HDI (0.775) कई विकसित देशों (जैसे अमेरिका, यूरोप) के बराबर है। यह उपलब्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता में दशकों के निवेश का नतीजा है। साथ ही सामाजिक सद्भाव भी इसके पीछे बड़ा कारण है। हालांकि यहां भी सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिशें होती हैं, लेकिन सरकार उनसे सख्ती से निपटती है। राज्य की 54.7% आबादी हिंदू, 26.6% मुस्लिम और 18.4% जनसंख्या ईसाई है। केरल ने साबित किया है कि विकास का रास्ता इंसान-केंद्रित नीतियों से होकर गुजरता है, न कि सांप्रदायिक विद्वेष से। इस कामयाबी की एक और वजह केरल की वाम सरकार द्वारा केन्द्र की मोदी सरकार के साथ समन्वय बनाकर रखना भी है। क्योंकि टकराव से कुछ हासिल नहीं हो सकता। विजयन सरकार ने यह संदेश देने की सफल कोशिश की है कि वैचारिक आग्रह विकास के आड़े नहीं आने चाहिए।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

संवैधानिक संस्था का अपमान सुनियोजित?

1960 के दशक में तत्कालीन जनसंघ के विधायक स्व. पडरीराव कृदत्त ने विधानसभा की तरफ जूता फेंका था, जिसकी समाज में भारी आलोचना हुई थी और जनसंघ को अपनी इस जूता संस्कृति के लिये अगले चुनाव में पराजय के रूप में कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मेरी जानकारी में उस समय के जनसंघ के एकमात्र नेता दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जो एकात्म मानववाद के प्रर्वतक बताये जाते हैं, ने ही इस घटना के सार्वजनिक बचाव का दुस्साहस किया था और भोपाल आकर इस आपराधिक, अनैतिक अलोकतांत्रिक कृत्य का मीडिया के माध्यम से बचाव करने का प्रयास किया था।

6 अक्टूबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश श्री गवई अपनी पीठ में सुनवाई कर रहे थे, तब एक वकील राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ पर जूता फेंका। यद्यपि वह उन तक नहीं पहुँच सका, परंतु श्री राकेश किशोर का जो लक्ष्य था वह उसने हासिल कर लिया। जस्टिस गवई ने पुलिस के द्वारा उसे पकड़े जाने के बाद रिहा करने को कहा और कहा कि मैं उसे माफ करता हूँ, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के अभिभाषक संघ ने उसकी सदस्यता समाप्त कर दी, यह दोनों निर्णय एक अर्थ में सही है कि जस्टिस गवई ने उसे माफकर अपना बड़प्पन सिद्ध किया और अभिभाषक संघ ने भी वकीलों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खीची है।

महात्मा गांधी तो दुनिया के ऐसे महात्मा थे जो अपनी हत्या का प्रयास करने वाले को भी दण्ड देना तो दूर उनकी आलोचना भी नहीं करते थे और इस अर्थ में जस्टिस गवई ने भी अपने आप को गांधीवादी सिद्ध किया है, हालांकि सांप्रदायिक सोच के लोग उनकी इस क्षमा को भिन्न-भिन्न तरीके से देखते हैं और प्रतिक्रियायें दे रहे हैं। उन विकृत मानसिकता के लोगों ने जस्टिस गवई के बड़प्पन को नकारने का प्रयास किया है और सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां डाली हैं कि उन्होंने इसलिये माफ कर दिया कि उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती, फिर गवाही देनी होती और उनसे कई प्रश्न पूछे जाते यह इन विकृत मानसिकता वाले समूहों का मानसिक दिवालियापन और अज्ञानता भी है, उन्हें यह पता नहीं है कि कोर्ट रूम की घटना के लिये मुख्य न्यायाधीश को रपट लिखने की जरूरत नहीं होती, जो पुलिस वहां डयूटी पर मौजूद थी, वह अपनी ओर से एफआईआर दर्ज करती, जो कि उसका वैधानिक दायित्व है और गवाही देने के लिये भी सीजेआई को भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोर्ट रूम के कर्मचारी सुरक्षा प्रहरी और उपस्थित वकील लोग गवाही दे सकते हैं।

ऐसी घटना, यह कोई पहली बार नहीं हुई है, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोग ऐसी घटनाओं को पहले भी अंजाम देते रहे हैं।

1960 के दशक में तत्कालीन जनसंघ के विधायक स्व. पडरीराव कृदत्त ने विधानसभा की तरफ जूता फेंका था, जिसकी समाज में भारी आलोचना हुई थी और जनसंघ को अपनी इस जूता संस्कृति के लिये अगले चुनाव में पराजय के रूप में कीमत भी चुकानी पड़ी थी। मेरी जानकारी में उस समय के जनसंघ के एकमात्र नेता दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जो एकात्म मानववाद के प्रर्वतक बताये जाते हैं, ने ही इस घटना के सार्वजनिक बचाव का दुस्साहस किया था और भोपाल आकर इस आपराधिक, अनैतिक अलोकतांत्रिक कृत्य का मीडिया के माध्यम से बचाव करने का प्रयास किया था।

एकात्म मानववाद वैसे भी उनकी खोज नहीं थी बल्कि वह भारतीय अतीत और वैदिक काल के दर्शन को अपने भाषण में उन्होंने उद्धृत किया था, जिसे जनसंघ के बुद्धिजीवियों ने उनके खाते में डाल दिया। वरना हमारे देश में कण-कण में भगवान हैं कि कहावत हजारों वर्ष से चल रही है, इसका मतलब ही होता कि न केवल मानव मात्र में बल्कि पशु,पक्षी, पत्थर सभी प्रकृति ईश्वर रूप हैं। श्री राकेश किशोर ने अपने कृत्य पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया बल्कि उन्होंने यह कहकर इसे सही सिद्ध ठहराने का प्रयास किया है कि वे जस्टिस गवई की उस टिप्पणी से आहत थे जिसमें उन्होंने (श्री राकेश किशोर के अनुसार) भगवान विष्णु का अपमान किया था और उनके शब्दों में सनातन का अपमान किया था। यह घटना जस्टिस गवई की पीठ में एक याचिका पर विचार करते समय हुई थी। एक याचिकाकर्ता ने यह याचिका पेश की थी कि खजुराहो में भगवान विष्णु की पत्थर की प्रतिमा जो अपने आप लंबे समय के कारण टूटकर गिर गई थी, उसे जोड़े जाने का या दूसरी प्रतिमा लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व विभाग को दें। जबकि पुरातत्व के कानून के अनुसार पुरातत्व विभाग किसी पुरातत्व की प्रतिमा को न जोड़ सकता है, न उस प्रकार की दूसरी प्रतिमा बना सकता है। वह प्रतिमा को खंडित होने से पहले अगर क्षय होने की जानकारी मिले तो उसे संभालने का प्रयास करता है, इस याचिका का निराकरण करते हुये जस्टिस गवई ने तीन बिंदु कहे थे-

1. वर्तमान कानून के अनुसार न्यायपालिका कोई आदेश नहीं दे सकती।
2. याचिकाकर्ता की याचिका प्रचारात्मक है।
3. उन्होंने हंसते हुये यह भी कहा कि इसके लिये तुम्हें भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करनी होगी।

इस तीसरी बात को लेकर श्री राकेश किशोर और उनकी तथाकथित सनातन जमातें जस्टिस गवई का विरोध कर रही हैं, उन्हें सनातन विरोधी बता रही हैं। वे वास्तव में इतने नासमझ हैं या स्थाई या लंबी सत्ता के कारण इतने मदहोश हो गये हैं कि किसी बात का अर्थ ही नहीं समझ सकते।

सैकड़ों वर्ष पहले आर्य समाज की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पत्थर में भगवान नहीं होते। शिवलिंग पर चढ़े हुये चूहे को देखकर ही उन्होंने यह टिप्पणी की थी और एक अर्थ में उन्होंने पाषाण पूजा को नकारकर वैदिक कालीन यज्ञ परंपरा को शुरू किया था तो क्या स्वामी दयानंद सनातन के भी खिलाफ थे? बल्कि वे यह कहकर समाज को तार्किकता की ओर ले जा रहे थे। वे धर्म और धार्मिक क्रियाओं की भी समाज उपयोगी दृष्टि से उपयोगी बता रहे थे और आज देश में करोड़ों आर्य समाज को मानने वाले हैं जिनका विश्वास पाषाण प्रतिमा में नहीं है तो क्या वे सनातन विरोधी हैं? सिख धर्म में भी, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है, पाठ होता है, प्रतिमा की पूजा नहीं होती तो क्या वे सनातन विरोध हैं? वैदिक काल में भी पाषाण प्रतिमा पूजा का कोई जिक्र नहीं है तो क्या वेद सनातन विरोधी है? और इस सनातन की व्याख्या करने वाले या उसका एकाधिकार यह इन चंद लोगों को कैसे प्राप्त हो गया? इन्हें भूलना नहीं चाहिये कि सिख कौम बहादुर कौम के गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों को दीवालों में चुन दिया, पर अपने धर्म को नहीं त्यागा।

जिन भगवान विष्णु के अपमान की बात कर श्री राकेश किशोर जस्टिस गवई पर कीचड़ उछाल रहे हैं उन्हें पता नहीं कि भगवान विष्णु का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु का अर्थ तो अहिंसा-पालनहार और क्षमा करने वाला होता है। हमारे देश की धार्मिक पुराणों व किवदंतियों में यह घटना बताई जाती है कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मारी थी और भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। इससे बड़ा अहिंसा, दया और क्षमा का क्या उदाहरण हो सकता है? परंतु राकेश किशोर जिसने केवल मतभिन्नता के आधार पर संविधान की सर्वोच्च पीठ को अपमानित करने के लिये जूता फेंका क्या वह भगवान विष्णु का न्याय हो सकता है? या भगवान विष्णु की आड़ में इस वैचारिक व कर्म की हिंसा को क्षमा किया जा सकता है।

जस्टिस गवई जब पीठ पर बैठते हैं तब वे एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं, जब वे सुनवाई कर रहे हैं तब वे व्यक्ति मात्र नहीं हैं बल्कि वे संवैधानिक पीठ के पर्याय हैं, जिसे भारतीय संविधान ने सर्वोच्च माना है। जिस प्रकार हमारे देश की हिंदू परंपराओं के दौरान व्यास पीठ पर बैठा व्यक्ति पीठ पर बैठने के बाद व्यास मुनि का पर्याय माना जाता है, उसी प्रकार संविधान पीठ पर बैठा व्यक्ति संविधान का पर्याय माना जाता है। श्री राकेश किशोर के द्वारा की गई हरकत को मैं व्यक्ति की त्रुटि मात्र नहीं मानता हूँ बल्कि मेरा यह अनुमान है कि जिस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या के पूर्व महात्मा गांधी के खिलाफ घृणा फैलाने का अभियान चलाया गया था, उसी प्रकार यह संविधान और न्यायपालिका के खिलाफ घृणा और नफरत फैलाने के अभियान की शुरुआत है और भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिये खिलाफ चल रहे छिपे अभियान का आरंभ है। कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि चूँकि 2 अक्टूबर को जस्टिस गवई की माता जी ने, नागपुर में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वार्षिक आयोजन में सहभागिता करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पति बाबा साहब अंबेडकर को मानते थे जिनकी विचारधारा, संघ से से भिन्न है अतरू मैं शामिल नहीं हो सकती। इसके बाद से ही....संकीर्ण व कटटरपंथी मानसिकता के समूहों में हलचल पैदा हुई और उन्होंने यह षडयंत्र सनातन के नाम पर जस्टिस गवई और सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को अपमानित कर संविधान विरोधी बहस का ही श्रीगणेश किया है।

मैं जस्टिस गवई की उदारता और बड़प्पन की प्रशंसा करते हुये भारत के सामाजिक संगठनों और नागरिक संगठनों और सनातन के मानने वालों से अपील करूँगा कि वे मुखर होकर ऐसी घटनाओं की निंदा करें और देश में एक ऐसा वातावरण बनाने की पहल करें, ताकि देश का जनमानस तार्किक, कानून प्रिय और संवैधानिक बने। तभी ऐसी संविधान विरोधी, घृणा और झूठ फैलाने वाली जमातों का मन बदल सकेगा।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, इस स्वाभिमान को सार्थक करना होगा

हम आध्यात्मिक दृष्टि से मानव भव में जन्म लेने पर स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, और उस पर भारतीय होने पर अतिरिक्त गर्व की अनुभूति से भर जाते हैं। इन्हीं संदर्भों में अनेकता में एकता का ताना-बाना भारतीयता के भाव से ओतप्रोत रहा होता है। अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज और परंपराओं के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र को अपने स्वाभाविक आचरण में आत्मसात करने के प्रति आम नागरिकों में समर्पण के भाव सदैव विद्यमान रहे हैं। राजनीतिक कारणों से क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर वर्ग भेद करते हुए क्षेत्रीय क्षत्रपों द्वारा क्षेत्रवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया। लेकिन आम नागरिकों की राष्ट्रवादी भावनाएं मुख्यधारा के विपरीत नहीं जा सकी। हमें अपनी विश्व वंदनीय गौरवशाली भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।

बावजूद इसके वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर हमें और अधिक चौकन्ना रहने की नितांत आवश्यकता है। देश की एकता और अखंडता को तार-तार करने की कोशिशें राजनीतिक संरक्षण पाती जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अलगाववाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के वर्चस्व को कम करने हेतु राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने का अनुक्रम जारी है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव बौद्धिक जुगाली की विषयवस्तु बनते जा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों की सत्ता अपनी अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही है।

राजनीतिक स्वार्थसिद्धि की ऐसी अंधी होड़ राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत करती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रवादी सोच को प्रोत्साहित करने की रीति नीति अपनाने की सख्त आवश्यकता है। राजनीति में नैतिक मूल्यों का विलोपन हो रहा है। व्यक्तिकेंद्रित राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों में सशक्त बनते जा रहे हैं। प्रकारांतर से अनेक राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर एकतांत्रिक व्यवस्था भी मूर्त रूप ले रही है। केंद्रीय नेतृत्व की खिलाफत करते हुए क्षेत्रीय मुद्दों को उछालकर आम नागरिकों की भावनाओं को भड़काने का दौर भी जारी है। ऐसे में कट्टर प्रांतवादी नजरिया कालांतर में राष्ट्रीय नजरिए के विपरीत न जा सके, इस संदर्भ में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। केंद्र व राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होने पर केंद्र तथा राज्य के संबंधों में तकरार स्वाभाविक रूप से हो सकती है। लेकिन ऐसी तकरार अपने अहम की तुष्टि हेतु होने लगे तब समस्याएं विकट होती जाती है। दशकों पूर्व केंद्र व राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु बहुतेरे प्रयास किए गए। लेकिन जैसे-जैसे क्षेत्रीय नेतृत्व की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती रही वैसे वैसे इन संबंधों में दूरियां बनने लगी। वर्तमान व्यवसायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रांतवासी परस्पर बेहतर तालमेल रखते हैं। कहीं कोई पूर्वाग्रह या कटुता के भाव नहीं होते। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को आपस में साझा करने की उत्कंठा का परिचय भी मिलता है।

परस्पर जिज्ञासु भाव के आकर्षण के चलते अलग अलग तौर-तरीकों को सीखने व समझने का व्यापक अनुभव पाने की भावना भी बलवती होती देखी जाती है। दरअसल जो भी कुछ अवरोध है,वह राजनीतिक स्तर पर है। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्तर पर कहीं कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और ना ही किसी प्रकार की असहमति है। बावजूद इसके जो समस्या है वह शत प्रतिशत राजनीतिक ही है। दरअसल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति के तौर-तरीकों में अमर्यादित आचरण और व्यवहार गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति की अंधी चाहत के चलते नैतिकता को ताक पर रख देने के निकृष्ट उदाहरण भी देखे जाते हैं। वास्तव में राजनीति के मूल स्वरूप में दिनोंदिन विकृति व्याप्त होती जा रही है।उक्त संदर्भों में राजनीति का शुद्धिकरण समय की मांग है। इस दिशा में विभिन्न शीर्ष राजनीतिक दलों के नेतृत्व को गंभीरतापूर्वक कदम उठाते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इस समय देश-प्रदेश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के मूल कारण की ओर दृष्टिपात करने पर समस्याओं की जड़ में राजनीतिक विकृति को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। दरअसल राष्ट्र के व्यापक हितों के मद्देनजर राजनीतिक स्वार्थसिद्धि की भावना का परित्याग ही देश के विकास को नए आयाम दे सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को दलीय हित से कहीं आगे राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। सत्ता के प्रति आतुरता के चलते राष्ट्रहित को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। अनेकता में एकता के ताने-बाने को और अधिक सशक्त धरातल दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

कुल मिलाकर तमाम विसंगतियों के बावजूद हम वैश्विक स्तर पर प्रगति की धारा में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में यदि सुधारवादी प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से हम विश्व की महाशक्ति के रूप में तीव्र गति से उभर कर सामने आ सकते हैं। हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है, शारीरिक एवं मानसिक श्रम शक्ति भरपूर है और दिनोंदिन हमारी प्रगति की रफ्तार भी तीव्र होती जा रही है। ऐसे में दृढ़संकल्प और इच्छाशक्ति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त तमाम विकृतियों का निदान करते हुए हम अप्रत्याशित उपलब्धियों को भी पा सकते हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह की प्रबलता का परित्याग करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल इस विषयक संज्ञान लेवे।वास्तव में विकास की प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए एकल एवं सामूहिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एक व्यक्ति समाज को क्या दे सकता है और समाज देश को क्या दे सकता है, इसका निर्धारण होने पर प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक समाज के समक्ष अलग-अलग दिशा और विधा में लक्ष्य सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया को निरंतर विस्तार देते हुए भारतीयों को मुख्यधारा के साथ जोड़कर देश के महाशक्ति की दिशा में बढ़ते कदमों को अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होना असंभव भी नहीं है, सदियों तक की दासता के पश्चात अब हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान एक भारतीय के नाते विश्व के किसी भी नागरिक से कम नहीं है। हमारी विश्व वंदनीय गौरवशाली भारतीय संस्कृति विश्व को एक नई दिशा दे सकती है, बशर्ते कि हम अपने आप को पहचान ले।

डर के आगे जीत है !

व्यंग्य

ब्रजेश कानूनगो

लेखक व्यंग्यकार हैं।

ऐसा व्यक्ति ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल काम है जो नितांत निर्भय हो। जहां किसी परिंदे ने डर के डैने कभी फड़फड़ाये ही नहीं हों। हर प्राणी किसी न किसी चीज से डरता है। कोई तो यह कहने तक से डरता है कि वह निडर है। कल से कह दिया और दुम दबाकर भागने की नौबत आ जाए तो फिर क्या होगा।

बहरहाल, डरना हमारा प्राकृतिक गुण है,सबके स्वभाव में थोड़ा बहुत शामिल है। डर है, तो डराने वाले भी हैं। हमेशा से दो तरह के हमारे हितैषी रहे हैं। एक वो जो डराने जैसा पुण्य का काम करते हैं, ताकि यह डर भाव जो सर्वदा प्रकृति प्रदत्त है कायम रह सके। दूसरे वे होते हैं जो डबल पुण्याई करते हुए सचेत करते हैं कि भाई डरो मत। दोनों तरह के लोग हमारे कल्याण के लिए ही सोचते हैं। ये तमाम व्यवसायी हमारी डर सम्पदा का दोहन करके लाभ कमाते हैं इनके गिरगिटिया हितोपदेश में आत्महित अधिक समाया होता है।

जैसे ही वक्त बदलता है, ये अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। डराने वाले डरो मत, डरो मत का उद्घोष करने लगते हैं और निर्भयता की सब्सिडी देने वाला, रंग बदल कर खुद डराने लग जाता है। ये लोग यह जताने में सफल भी हो जाते हैं कि इनमें लोकोपकार की भावना कूट-कूट कर भरी है। ये भलीप्रकार जानते हैं कि भय समस्त प्राणी मात्र का स्थायी भाव है, इसी भाव को ये भरपूर भाव देते हैं और लोकतंत्र की मंडी में ऊंचे भाव पर इसकी बोली लगा देते हैं।

दरअसल, जो डराते हैं, वे हमारे हितैषी हैं।डरने के बाद ही आदमी मजबूत होता है। उसके भीतर साहसी हो जाने की आकांक्षा बलवती होने लगती है। असीम शक्ति का संचार होता है। अधिक बड़ी और भयावह स्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित होने लगती है। भय की एंटी बॉडीज हमारे भीतर बनने लगती हैं।डर के आगे जीत है। यदि विजेता बनना चाहते हैं तो डर का सामना करना होगा। डर होगा तब ही आदमी डरेगा। यदि डर ही नहीं होगा तो वह किससे डरेगा। डर पर विजय के उसके संघर्ष का क्या होगा? संघर्षों से ही जीत का सच्चा आनन्द मिलता है। बिना डरे कुछ हासिल हो जाए तो मजा नहीं। इसलिये डर भी जरूरी है,डरना भी जरूरी है। डर से मुक्ति का संघर्ष भी जरूरी है।

डर का कोहरा छटने के बाद सूरज के दर्शन होते हैं। डर रात का अँधेरा है, सुबह उजियारा लाती है।सूरज की रौशनी में सब साफ़ दिखाई देने लगता है। क्या मोहक है और क्या डरावना है। अँधेरे में तो सुंदर भी खौफ़नाक हो जाता है। खुद आदमी अपने अक्स से डर जाता है। भय से भयभीत मत होइए। इसका स्वागत कीजिये। भय से कैसा डर? आचार्य गब्बर सिंह कह गए हैं- 'जो डर गया, समझो मर गया।' निर्भय होकर डर से दो-दो हाथ कीजिये।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

छठ पूजा पर विशेष

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

(लेखक व्यंग्यकार)

एक पर्व नहीं है, महापर्व है छठ पूजा

दिवाली के बाद छठ पूजा का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान घर से लेकर घाटों तक बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस दौरान छठी मैया की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसर छठी मैया की उपासना और व्रत करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोकपर्व हैं जो अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। सूर्य षष्ठी के महत्व को देखते हुए इस पर्व को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल की तराई समेत देश के उन तमाम महानगरों में मनाया जाता है। जहां-जहां इन प्रांतों के लोग निवास करते हैं। यही नहीं, मॉरिशस, त्रिनिडाड, सुमात्रा, जावा समेत विदेशों में भी भारतीय मूल के प्रवासी छठ पर्व को बड़ी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं। डूबते सूर्य की विशेष पूजा ही छठ का पर्व है। चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। छठ पर्व की सांस्कृतिक परम्परा में चार दिन का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भैया दूज के तीसरे दिन यानि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ हो जाते है। व्रत के पहले दिन को नहा-खा कहते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ है स्नान के बाद खाना। इस दिन पवित्र नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं। वैसे तो यह पर्व मूल रूप से गृहिणियों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन आजकल पुरुष भी इसमें समान रूप से सहयोग देते हैं।

छठ पूजा का व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। इस व्रत को करने से निःसंतान दंपत्तियों को संतान सुख प्राप्त होता है।छठ पर्व को किसने शुरू किया इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशिर्वाद प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में छठ पूजा की जाती है। छठ का पौराणिक महत्व अनादिकाल से बना हुआ है। रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी। महाभारत काल में कुंती ने भी सरस्वती नदी के तट पर सूर्य पूजा की थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें पांडवों जैसे पुत्रों का सुख मिला था। द्रौपदी ने भी हस्तिनापुर से निकलकर गढ़ गंगा में छठ पूजा की थी। छठ पूजा का सम्बंध हठयोग से भी है। जिसमें बिना भोजन ग्रहण किए हुए लगातार पानी में खड़ा रहना पड़ता है। जिससे शरीर के अशुद्ध जीवाणु परास्त हो जाते हैं।

छठ पर्व की परम्परा में वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है। जिस समय धरती के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है और दक्षिणायन के सूर्य की अल्ट्रावॉइलट किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इन दूषित किरणों का सीधा प्रभाव जनसाधारण की आंखों, पेट, त्वचा आदि पर पड़ता है। इस पर्व के पालन से सूर्य प्रकाश की इन पराबैंगनी किरणों से जनसाधारण को हानि न पहुंचे। इस अभिप्राय से सूर्य पूजा का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसके साथ ही घर-परिवार की सुख- समृद्धि और आरोग्यता से भी छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित सभी परिजनों के लिए मंगल कामना से भी जुड़ा हुआ है।लोक परम्परा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मईया का संबंध भाई-बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। छठ पूजा अथवा छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और लोक गाथाओं पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत के आदिकालीन सूर्यवंशी राजाओं का यह मुख्य पर्व था। छठ के साथ स्कंद पूजा की भी परम्परा जुड़ी है। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की छह कृतिकाओं ने स्तनपान करा रक्षा की थी। इसी कारण स्कंद के छह मुख हैं और उन्हें कार्तिकेय नाम से पुकारा जाने लगा। कार्तिक से संबंध होने के कारण षष्ठी देवी को स्कंद की पत्नी देवसेना नाम से भी पूजा जाने लगा। महापर्व छठ हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ना केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की अराधना की जाती है। पर्व का प्रारंभ नहाय-खाय से होता है, जिस दिन व्रती स्नान कर अरवा चावल, चना दाल और कद्दू की सब्जी का भोजन करते हैं। नहाय-खाय के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी के दिनभर व्रती उपवास कर शाम में रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पूजा को खरना कहा जाता है। इसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को उपवास रखकर शाम को अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन यानी सप्तमी तिथि को सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके व्रत तोड़ा जाता है।

छठ पूजा के व्रत को जो भी रखता है। वह इन दिनों में जल भी नही ग्रहण करता है। इस व्रत को करने से सुख-समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पूजा वैसे तो मुख्य रुप से सूर्य देवता की पूजा की जाती है। लेकिन साथ ही सूर्य देव की बहन छठ देवी की भी पूजा की जाती है। जिसके कारण इस पूजा का नाम छठ पूजा पड़ा। इस दिन नदी के तट में पहुंचकर पुरुष और महिलाएं पूजा-पाठ करते है। साथ ही छठ माता की पूजा को आपके संतान के लिए भी कल्याणकारी होती है।

न्याय और कानून

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक

केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है। लेकिन, ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। धारा 6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 राज्य एवं केंद्र सरकारों ने उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त करने की बात करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एक बार जांच पूरी हो जाने, आरोप पत्र दाखिल हो जाने और मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ऐसी आपत्तियों का इस्तेमाल कार्यवाही को अमान्य करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका अपवाद वहां होगा जहां संज्ञान लेने से पहले ही रद्द करने की याचिका लंबित हो। यह जानना दिलचस्प है कि आखिर क्यों सीबीआई को राज्य से अन्वेषण के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है? यह भी जानना चाहिए कि अगर सीबीआई किसी पर कार्यवाही करती है तो उनके क्या अधिकार होते हैं? सीबीआई अर्थात् केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है तथा यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। यह संस्था भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करती है। लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। सीबीआई भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसकी अपराध सिद्धि दर 65 से 70 प्रतिशत है। अत: इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

सीबीआई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया था ताकि युद्ध में संबंधित खरीद मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण के लिए एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संथानम समिति (1962-1964) द्वारा की गई थी। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा इस एजेंसी का गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी व गबन और सामाजिक अपराधों (विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी) के अन्वेषण के लिए किया गया। कुछ समय बाद सीबीआई को चर्चित हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किये गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायित्व भी सौंपा जाने लगा।

केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है। लेकिन, ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। धारा 6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 राज्य एवं केंद्र सरकारों ने उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त करने की बात करती है। सीबीआई एक विशेष पुलिस स्थापना इकाई है। अत: उसे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। यह सहमति दो प्रकार की होती है। एक केस विषिष्ट सहमति और दूसरी, सामान्य सहमति। यद्यपि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित होता है। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद यह एजेंसी राज्य सरकार के कर्मचारियों या हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जांच भी कर सकती है।

दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना उस राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा। जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिये केस के आधार पर प्रत्येक बार सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यह सीबीआई द्वारा निर्बाध

जांच में बाधा डालती है। 'सामान्य सहमति' सामान्यत: सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में मदद के लिये दी जाती है, ताकि सीबीआई की जांच सुचारू रूप से चल सके और उसे बार-बार राज्य सरकार के समक्ष आवेदन न करना पड़े। लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐसी सहमति दी गई है। यदि राज्यों द्वारा सहमति नहीं दी गई तो इसे सीबीआई को प्रत्येक मामले में जांच करने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक होता है।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई द्वारा राज्य की सहमति न लेने के संबंध में आपत्तियों के बारे में अदालत ने कहा कि, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत सहमति के अभाव का मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद उठाया जाना चाहिए। एक बार जांच पूरी हो जाने, आरोप पत्र दायर हो जाने और सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिए जाने के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेने वाले आदेश की वैधता को कम करने के लिए ऐसी कोई दलील नहीं दी जा सकती। यह आधार हो सकता है कि इससे न्याय का गंभीर हनन होता है। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई हो और रद्द करने की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दायर कर दिया गया हो। ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति के पास यह तर्क देने का कुछ औचित्य हो सकता है कि रद्द करने की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दायर करने से उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मध्य प्रदेष उच्च न्यायालय की इन्दौर पीठ का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अभियुक्त नंबर 1 और 3 के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहपठित 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को तर्कहीन बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति होती कि निरस्तीकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दाखिल किया गया होता तो अभियुक्त यह दलील देता कि निरस्तीकरण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आरोप पत्र दाखिल करने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी सहमति न होने का तर्क दे सकता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी की निरस्तीकरण याचिका को स्वीकार करना उच्च न्यायालय की गलती थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक विवादों का समय से पहले ही निपटारा किया था, जिन्हें साक्ष्यों के माध्यम से ट्रायल कोर्ट को जांचने के लिए छोड़ देना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि आरोपों के गुण-दोष पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की भूमिका निभाते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया। कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं, जिन्हें ट्रायल कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पुन: स्थापित कर दिया गया। अभियुक्तों को निर्देष दिया गया कि नियत तिथि को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो तथा ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करे।

स्मृति- शारदा सिन्हा

विनोद कुमार विक्की

युवा रचानाकार

छठ महापर्व के गीतों में बिहार कोकिला का स्वर

उत्तर भारत के किसी भी घर में यदि विवाह, मुंडन या छठ का अवसर हो, तो शारदा सिन्हा की आवाज़ बिना उस पर्व की पूर्णता संभव नहीं। वर्ष 1974 से लोकगीत गायन आरंभ करने के बाद, 1978 में उनका पहला रिकॉर्डेड छठ गीत 'उग हो सुरुज देव' ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

इ से संयोग कहें या प्रकृति की अद्भुत लीला,जिस आवाज़ ने उत्तर भारत के महापर्व छठ की महिमा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, वही स्वर पिछले वर्ष इसी पर्व के प्रथम दिन सदा के लिए मौन हो गया।

1 अक्टूबर 1952 को सुपौल जिले के हुलास गाँव में जन्मी माँ शारदे की मानस पुत्री शारदा सिन्हा ने अपनी मर्मस्पर्शी आवाज़ को भारतीय लोकसंगीत की अनमोल धरोहर के रूप में छोड़ते हुए 05 नवंबर 2024, छठ महापर्व के प्रथम दिन, इस संसार से विदाई ली। छठ के प्रति उनकी गहन आस्था का ही परिणाम था कि उनके जीवन का अंतिम गीत — 'दुखवा मिटाई छठी मइया' भी इसी पर्व को समर्पित था। बीते वर्ष जारी यह गीत उनकी वही जादुई दिलकश आवाज़ लिए हुए था, जिसने दशकों से लोकसंगीत के हर सुर को जीवन दिया।

संगीत में पीएचडी उपाधि प्राप्त शारदा सिन्हा लोकगीतों की जादूगरनी और भारतीय लोकसंगीत की निर्विवाद मल्लिका थीं। उनके संगीत योगदान को देश-विदेश में सराहा गया। 1991 में पद्मश्री पुरस्कार, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2015 में बिहार सरकार सम्मान 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण सम्मान सहित अनेक संगीत सम्मानों से नवाजा गया है।

मैथिली, भोजपुरी और हिन्दी—तीनों भाषाओं में अपनी मधुरता से गीतों को अमर करने वाली शारदा सिन्हा को स्नेहपूर्वक 'बिहार कोकिला' कहा गया।

उत्तर भारत के किसी भी घर में यदि विवाह, मुंडन या छठ का अवसर हो, तो शारदा सिन्हा की आवाज़ बिना उस पर्व की पूर्णता संभव नहीं। वर्ष 1974 से लोकगीत गायन आरंभ करने के बाद, 1978 में उनका पहला रिकॉर्डेड छठ गीत 'उग हो सुरुज देव' ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

इसके बाद उनके असंख्य गीत जैसे — 'केलवा के पतवा पर','कांच ही बांस के बहंगिया',बहंगी लचकत जाए','हे छठी मइया','नदिया के तीरे','सूरज के रथ मइया','मैया हे गंगा मइया' हर वर्ष कार्तिक और चैत्र मास में देश के कोने-कोने में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुंजायमान होते हैं। उनकी गायकी में आस्था, मातृत्व और लोक-संवेदना का अद्भुत संगम है, जो व्रती और श्रद्धालुओं को आज भी भाव-विभोर कर देता है।

फिल्म संगीत में भी शारदा सिन्हा ने भारतीय नारी की कोमल भावनाओं को शाश्वत बना दिया। 'मैंने प्यार किया' फिल्म में असद भोपाली का लिखा गीत — 'मोहे लागे प्यारे, सभी रंग तिहारे...' उनकी आवाज़ में प्रेम और समर्पण की पवित्रता का प्रतीक बन गया। वहीं 'हम आपके हैं कौन' का प्रसिद्ध विदाई गीत —'बाबुल जो तूने सिखाया, जो तुझसे पाया, सजन घर ले चली...' रुँधे गले और भावनाओं से भीगे स्वर में उन्होंने हर बेटी की विदाई को अमर कर दिया। उनके वैवाहिक पारंपरिक गीत जैसे 'दुल्हिन', 'मेंहदी', 'पीरितिया' आदि आज भी सांस्कृतिक गरिमा और शालीनता के प्रतीक हैं।

आज जब तथाकथित लोकगायकों द्वारा अश्लीलता और द्विअर्थीपन से भोजपुरी संगीत अपनी पहचान खोता जा रहा है, ऐसे समय में शारदा सिन्हा के गीत 'पटना से बैद्या बुलाय दा...','ले ले अइह हो पिया सेनूर बंगाल के...' भोजपुरी गीत-संगीत की समृद्ध, सरस और संस्कारित परंपरा के जीवंत प्रमाण हैं।

छठ पूजा उनके बिना अब अधूरी-सी लगती है। फिर भी, घाटों पर गूंजते उनके गीतों में वही आस्था, वही अपनापन और वही आत्मा आज भी विद्यमान है। व्रती जब 'केलवा के पतवा पर...' गुनगुनाते हैं, तो लगता है जैसे शारदा जी की आत्मा लोक-स्वर के रूप में अब भी हमारे बीच है।

अनुकरणीय

आशीष दशोत्तर

लेखक साहित्यकार हैं।

धर्म के बीच एक पुल बनाती पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ की 'गीता भारती'

आ ध्यात्मिक विचार असीम होते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं । इनके भीतर जो जितना डूबता जाता है उसे उतना ही आनंद आता है । आध्यात्मिक जीवन और दर्शन वस्तुत: हमारे परिवेश को निर्मित करते हैं । जब हम सब दूर से निराश हो जाते हैं तो आध्यात्मिकता में ही एक नई राह दिखाई देती है।

रचनाशीलता के विभिन्न दौर से गुज़रते हुए हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर गहरी पकड़ और आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक रचनाकार पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ ने श्री मद्भागवत गीता पर आधारित अपनी रचना 'गीता भारती' का पहला अध्याय पूरा कर लिया है। गीता के 18 अध्याय और 786 छंदों को काव्यात्मक रूप में लाने की शुरुआत 54 छंदों के साथ गतिमान है। इससे पहले उन्होंने कुरान शरीफ़ से प्रेरित 18 अध्यायों की 10,000 छंदों में रचना पूरी की है, जिसे ले कर संगीतकार ए.आर. रहमान 'सूरह रहमान' पर आधारित 40 छंदों की रचना पर काम कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री अनूप जलोटा भी पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ के पदों को अपने स्वरों से सजा रहे हैं।

पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ ने अभी गीता के प्रथम अध्याय, 'अर्जुन-विषाद-योग' के 46 श्लोकों को 54 काव्यात्मक पदों में रूपांतरित किया है। इसे एक वीडियो एल्बम के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक एपिसोड में छह पद शामिल होंगे। भागवद गीता से प्रेरित 'गीता भारती' में 786 पद 131 एपिसोड होंगे।यह एक अनूठा और महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो उनके काव्य-प्रेम, आध्यात्मिक गहराई, और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। गीता के प्रथम अध्याय के 46 श्लोकों को 54 काव्यात्मक पदों को रचनात्मक विस्तार दे कर उन्होंने प्रत्येक श्लोक के भाव को गहराई से आत्मसात किया और उसे काव्य की लय में ढाला।

उदाहरण के लिए कुछ पदों का काव्य रूपांतरण देखिए।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
धर्मस्यास्तु ध्रुवं ज्योति: संभवामि युगे युगे॥
आओ सत्यमेव जयते कहे और करे सद्कर्म।
सार्थक हो जाए सृष्टि पर आना जनम जनम।।
यूं तो विश्व के सब धर्मग्रंथ ही है कर्म प्रधान,
परन्तु गीता का आगमन और उदगम सर्वप्रथम।।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
भीष्म पितामह ने कर दिया युद्ध का सूत्रपात।
नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज उठे तत्पश्चात।
शंख नगाड़े तुरही ढोल भेरी का मच गया शौर,
उनका यह शौर भयंकर मचा रहा था उत्पात।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
आए माधव युद्ध भूमि में अर्जुन के संग प्रकट।
दिव्य शंख के साथ दिव्य अश्वो पर गये वो डट।
गूंज उठा शंखनाद उनका, हलचल हो गई भारी,
कौरव पांडव में युद्ध ठन गया, सम्मुख था संकट।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
स्वजन से स्वजन का सामना, माधव प्रत्यक्ष तौर प्रकट।
बना रहा है रण भूमि का वातावरण, माधव और विकट।
गुरू, पितामह, पुत्र सभी रणभूमि में हो रहें है दृष्टिगोचर,
है माधव क्युं द्रवित न हो, मन भले ही हो कितना जीवट।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
पार्थ बोले है मधुसूदन, मन है अजीब कशमकश में।

बंधु बांधव देख सामने, मस्तिष्क भी ही असमंजस में।
मामा, ससुर, पौत्र, साले सब है अपने नाते रिश्तेदार,
इन पर प्रहार करने का माधव, साहस नही है बस में।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
अधर्म घातक है, ध्यान रखना है नारी का हमें विशेष।
वर्ना वर्णसंकर की उत्पत्ति का भी, झेलना होगा क्लेश।
संस्कृति, संस्कार, सभ्यता नष्ट होने का न रहे संशय,
मार्ग ऐसा चले हम माधव, जिससे धर्म रहे हमारा शेष।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
विनाशकारी है कुल परंपरा विनष्ट होना बोले पार्थ।
दुष्कर्मो से अवांछित संतान उत्पत्ति ही है यथार्थ।
जाति-धर्म और रीति-रिवाज सब धूल धूसरित होते,
पारिवारिक कार्य विनष्ट होते विचलित होता परमार्थ।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
पार्थ बोले, हे माधव हाय! पाप कर रहें स्वार्थवश।
राज्य लोभ सुख की चाह में, सत्य न किया विमर्श।
स्वजन पर ही शस्त्र संभाले, कुल मर्यादा की प्रदुषित,
कैसे बचे सनातन सत्य, कैसे त्यागे हम व्यर्थ संघर्ष।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
पार्थ बोले है जनार्दन, सुनो मेरे मन की पुकार।
मैं निहत्था बिना प्रतिकार, सहुं धृतराष्ट्र का वार।
स्वजन से रहू अछूता, सनातन धर्म भी न हो नष्ट,
ऐसी मृत्यु है आदर्श, जो हो कुल सम्मत स्वीकार।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।
और धनुर्धर अर्जुन, मन शोक से व्याकुल भारी।
बोले हे पार्थ, सुनो मेरे अंतस की व्यथा भी सारी।
रथ पर बैठ, धनुष त्यागा, छोड़कर युद्ध संनाद,
ज्यूं दयालू, निर्लिप्त, करें आत्मज्ञान की तैयारी।
परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म।
फल की चिंता न करो, कर्म है मानव धर्म।
कर्म करो बस कर्म करो।

इस तरह गीता के श्लोकों का पंडित मुस्तफा आरिफ ने लयात्मकता के साथ और गीतात्मकता को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया है। यह कार्य बहुत कठिन भी है और महत्वपूर्ण भी। कठिन इसलिए कि आसान शब्दावली में किसी पूर्व रचना को ढालना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और उस पर उसे पूरी तुकबंदी के साथ पूर्ण करना, किसी नई रचना को लिखने से अधिक परिश्रम वाला है । यह कार्य इसलिए भी सराहनीय है कि इसने आध्यात्मिक चेतना को जगाने के अपने महत्वपूर्ण मिशन को आगे बढ़ाया है।

पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ धार्मिक दूरियों को कम करने में लगे हैं । वे यह कहते हैं कि प्रत्येक धर्म का मूल विश्व शांति ही है। हर धर्म की प्रार्थनाएं शांति का संदेश ही देती हैं । यह संदेश जन-जन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है।

इसी संदेश को पहुंचाने के लिए ही वे जिस शिद्दत से कुरान शरीफ़ की आयतों का अनुवाद कर रहे हैं, उसी गहनता के साथ गीता के श्लोकों का भी अनुवाद कर रहे हैं ।

यह अनुवाद किताब के शक्ल में तो हमारे सामने आ ही रहा है, ऑडियो और वीडियो के रूप में भी इस देश के महत्वपूर्ण गायक - संगीतकार प्रस्तुत कर रहे हैं ।आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर पंडित मुस्तफ़ा आरिफ़ का यह प्रयास निस्संदेह प्रेरणादायक है। आने वाले समय में जब यह कार्य पूर्ण होगा तब इस कार्य की आभा बहुत दूर तक फैलेगी,हमें यक़ीन है ।

कांक्रीट की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल, पांच मजदूर कर रहे करोड़ों का कार्य

घटिया मटेरियल से हो रहा, एक करोड़ सात लाख रुपये के नपा भवन का निर्माण

बैतूल/ मुलताई। नगरपालिका मुलताई कार्यालय के ठीक बाजू में 1 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से बन रहे नवनिर्मित नगर पालिका भवन में नियमों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण एवं निम्न स्तरीय सामग्री के उपयोग को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। किंतु इसके बावजूद भी निर्माण प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों पार्षदों ने भी सर्फेस भरण में मुरम के बजाय मिट्टी और मलबा भरे जाने की शिकायत की थी, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके चलते करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे नगर पालिका भवन के निर्माण पर अभी से प्रश्नचिन्ह लग गए हैं। जानकार बताते हैं कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में जमकर नियमों की अनदेखी की जा रही है और रोचक तथ्य यह है कि यह सब उस स्थान पर हो रहा है, जहां नगर पालिका से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि लगभग प्रतिदिन कार्यालय आते हैं और अधिकारी- कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं। फिर भी कोई ठेकेदार से यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि जो कंक्रीट बनाया जा रहा है उसके क्यूब भरे जा रहे हैं या नहीं। भुगतान के लिए लगाई जा रही सामग्री जांच रिपोर्ट कहां से आ रही है। कंक्रीट में मिट्टी युक्त बजरी का उपयोग क्यों हो रहा है और यह किस साइज की है।

कांक्रीट में हो रहा है बजरी और डस्ट का उपयोग

नगर पालिका परिसर में हो रहा घटिया निर्माण, उपयंत्री ने कहा सुधार करो

घटिया निर्माण की जानकारी मिलते ही जब हम नगर पालिका नवनिर्मित भवन के स्थल पर पहुंचे तो जो देखा वह चौंकाने वाला था। करोड़ों रुपये के कार्य का ठेका, जिस ठेकेदार को दिया गया है, उसने भी यह कार्य पेटी कांट्रेक्ट पर किसी और को दे दिया है। वहाँ मात्र पांच मजदूर और एक छोटी सी मिक्सर मशीन के भरोसे भवन के पिलर भरे जा रहे हैं। कंक्रीट मिक्सर में बजरी, डस्ट जिसमें मिट्टी मिली है, उसका उपयोग किया जा रहा है। गिट्टी का कोई मानक साइज नहीं है। डस्ट बजरी और बारीक गिट्टी के साथ बहुत कम मात्रा में सीमेंट डाला जा रहा है। कंक्रीट में इतना अधिक पानी है कि मसाला गीली मिट्टी की तरह फैल रहा है, जबकि पिलर किसी भी निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनमें सॉलिड कंक्रीट व वाइब्रेटर का उपयोग आवश्यक है। यहां वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा। पांच मजदूर मसाला बनाते हैं, मशीन में मटेरियल डालते हैं और पूर्व में बने पिलर की सेंट्रिंग हटाते हैं। मसाला कई घंटे रखने के बाद उपयोग किया जा रहा है जिससे कंक्रीट सॉलिड हो जाती है। इस संबंध में जब शिकायत नगर पालिका उपयंत्री महेश शर्मा से की गई, तो उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद ठेकेदार के लोगों को वाइब्रेटर लगाने, बजरी-डस्ट का कंक्रीट में उपयोग न करने और कंक्रीट क्यूब भरने के निर्देश दिए।

विधायक के प्रयास से स्वीकृत हुआ नगर पालिका भवन- बीते दो दशक से मुलताई नगर पालिका कार्यालय खस्ताहाल भवन में संचालित हो रहा था। काफी प्रयासों के बाद विधायक चंद्रशेखर देशमुख के प्रयास से 1 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण को स्वीकृति मिली है। निर्माण का ठेका तनुष्का कंस्ट्रक्शन भोपाल को मिला है। जानकारों के मुताबिक यह वही ठेकेदार है, जिसने पहले 10 करोड़ की लागत से सडक और नालियों का निर्माण किया था और जो एक वर्ष बाद ही टूटना शुरू हो गए थे। आज तो उनके अवशेष भी ढूंढना मुश्किल है। जानकर लोगों का मानना है कि ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण निर्माण में सुधार करवाना संभव नहीं हो पा रहा। निर्माण को लेकर लोगों का उत्साह अब आक्रोश में बदलने लगा है और निर्माण ठेका प्रक्रिया की जांच की मांग भी लगातार उठ रही है।

इनका कहना -

हमने ठेकेदार के लोगों को कार्य में सुधार करने, कंक्रीट में बारीक बजरी का उपयोग न करने, पिलर भराई में वाइब्रेटर का उपयोग करने और बनाए गए कंक्रीट के क्यूब भरने के निर्देश दिए हैं।

महेश शर्मा,

आस्था का महापर्व छठ आज, अस्त होते सूर्यदेव को पड़ेगा पहला अर्घ्य

बैतूल। आस्था और विश्वास का महापर्व छठ आज सारनी पाथाखेड़ा क्षेत्र में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज शाम अस्त होते सूर्यदेवता को पहला अर्घ्य समर्पित किया जाएगा एवं मंगलवार की सुबह उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। वैसे तो सारनी पाथाखेड़ा क्षेत्र में छठ पर्व 60 के दशक से ही मनाया जाता है जिसकी शुरुआत पाथाखेड़ा के प्राचीन शिव मंदिर से हुई थी लेकिन सतपुड़ा डेम पर सामूहिक रूप से छठ पूजा महोत्सव का आयोजन 2005 से किया जा रहा है। इसके पहले पाथाखेड़ा में रहने वाले उतर भारतीय छठ पूजा करने अपने परिवार के साथ नांदिया घाट या धाराखोह नदी घोड़ाडोंगरी जाते थे।

आज भी शोभापुर एवं बगडोना कालोनी के कई परिवार नांदिया घाट जा कर छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा का सबसे बड़ा आयोजन सतपुड़ा डेम के पास होता है, जहाँ बडी संख्या में छठ मनाने लोग एकत्रित होते हैं। आयोजन समिति से जुड़े कमलेश सिंह ने बताया कि भोजपुरी एकता मंच के बैनर तले 2005 से सामूहिक रूप से छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, तब नगरपालिका अध्यक्ष मनोज डेहरिया एवं उस समय की परिषद द्वारा यहाँ की व्यवस्थाओं एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक छोटे से बजट का आवंटन किया था। पिछले दो दशक से यह परम्परा अनवरत चल रही है। पिछले 20 सालों में छठ पूजा का स्वरूप काफी बड़ा हो चुका है।

छठ घाट पर लाइटिंग, बैठक व्यवस्था, घाट की साफ सफाई एवं बैठक व्यवस्था नपा परिषद द्वारा की जाती है। भोजपुरी एकता मंच द्वारा सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रसाद वितरण किया जाता है। इस वर्ष भी नगरपालिका द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रकार का इंतजाम किया गयाहै। सोमवार की शाम एवं मंगलवार की शाम स्थानीय एवं बाहर से आये कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। आकर्षक झांकियों के साथ आतिशबाजी होगी। भोजपुरी एकता मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा ठेकुआँ का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

जिले के 1593 बूथों पर सुनी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात

बैतूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 127 वॉ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के 1593 बूथो पर सुनने और देखने की व्यवस्था की गई। मुलताई विधानसभा के

प्रभातपटटन मंडल के रायआमला बूथ क्रमांक 175 पर केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार सम्मिलित हुए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सतीश धाकड, जनपद सदस्य नितेश काले, सरपंच सूमन डांगे, पूर्व सरपंच जगन्नाथ गव्हाडे, मंगल नरवरे सहित बूथ समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के पश्चात कहा कि मन की बात का प्रसारण में मोदी जी राष्ट्र की बात करते है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा-पीढियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला गया। श्री उइके ने कहा कि साथियों, अब समय बदल रहा है, तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि इस विशेष कड़ी में मोदी जी ने लोक आस्था के महापर्व छठ, देवभाषा संस्कृत के संरक्षण, वन्दे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने की ऐतिहासिक उपलब्धि, तथा लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150 वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी जैसे अनेक प्रेरक विषयों पर अपने विचार साझा किए।

भार्गव समाज के दीपावली मिलन में उज्जैन अधिवेशन को लेकर हुआ मंथन

बैतूल। भार्गव समाज बैतूल का दीपावली मिलन समारोह गत दिवस जितिन-प्राची भार्गव के सिविल लाइन्स, बैतूल स्थित निवास

पर संपन्न हुआ। मिलन समारोह में अखिल भारतीय भार्गव सभा के उज्जैन में दिसम्बर माह में होने वाले वार्षिक अधिवेशन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समाज के अध्यक्ष दीपक भार्गव ने जानकारी दी कि उज्जैन में समाज का वार्षिक अधिवेशन 20-21 एवं 22 दिसम्बर को होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज के जिन प्रतिभावान बच्चों ने किसी भी विधा में महारत हासिल कर पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनके लिए अखिल भारतीय भार्गव सभा की वेबसाइट पर फार्म उपलब्ध है जिसे भरकर अखिल भारतीय भार्गव सभा को भेजना है। ऐसे बच्चों को अखिल भारतीय सभा द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि भार्गव सभा बैतूल की मासिक बैठक रविवार को ही हुआ करेगी। बैठक में भार्गव सभा के सभी सदस्य उपस्थित थे। दीपावली मिलन समारोह में जितिन-प्राची द्वारा रात्रि भोज का आयोजन रखा गया था। सभी ने दीपावली मिलन समारोह के बेहतरीन आयोजन के लिए जितिन-प्राची को धन्यवाद दिया है। मिलन समारोह में गोपाल, अनिल, मनोज, प्रमोद, सुधीर, मयंक, निधिष, राजेश, चेतन, मयूर, गौरव, मुदित, प्रखर, शिवम, प्रथम, मौलिक, यजत, भार्गव एवं महिला सभा की कविता, दीपा, मीरा, दीप्ति, सुनीता, रेणु, श्वेता, रश्मि, अश्विनी, सोनल, तन्वी, रियोना भार्गव उपस्थित रहे।

बाथरूम में गिरी महिला की इलाज के दौरान मौत

बैतूल। शुगर लेवल गिरने से घर के बाथरूम में गिरी 55 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की पहचान अमदर निवासी सुनीता पति गुलाबराव सातपुते के रूप में हुई है। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, सुनीता को शुगर और बीपी की समस्या थी। 24 अक्टूबर को शुगर का स्तर कम होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वे बाथरूम में गिर गईं। इस घटना में उनके बाएं पैर में अंदरूनी चोट आई थी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां दो दिन तक उनका इलाज चला। रविवार रात उनकी हालत बिगडने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल पुलिस चौकी ने घटना का पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया।

जिले के 821 बूथों पर सुनी गई मोदी की मन की बात, विधायक, जिला अध्यक्ष हुए शामिल

धार । विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का127वें संस्करण रेडियो कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती के नेतृत्व में रविवार को जिले की धार,बदनावर और सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 18 मंडलों के 821 बूथो पर सुनने और देखने की व्यवस्था की गई।

भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने धार विधानसभा के पीथमपुर में वार्ड क्रमांक 16 बूथ क्रमांक 257 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद मन की बात कार्यक्रम को भाजपा पदाधिकारी की उपस्थिति में सुना। इस दौरान जिला मंत्री जीवन रघुवंशी भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश जायसवाल प्रभारी सुभाष जायसवाल पिंटू जायसवाल अमृत जैन

कुंदनसिंह पंवार उपस्थित रहे। वही धार विधायक नीना वर्मा ने धार नगर के बूथ नंबर 59 अर्जुन कॉलोनी में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विशाल निगम मंडल महामंत्री अमित शर्मा बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता के साथ श्रवण किया।

भाजपा जिलाध्यक्ष निलेश भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के पश्चात कहा कि मन की बात का प्रसारण भारत की बात का प्रसारण बन चुका है। छठ पूजा लोक आस्था, पर्यावरण और परिवार की एकजुटता का पर्व है। यह सूर्य उपासना के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। वोकल फॉर लोकल' की भावना से हर भारतीय आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस विशेष संस्करण में लोक आस्था के महापर्व 'छठ', देवभाषा संस्कृत के संरक्षण, 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने की ऐतिहासिक उपलब्धि, तथा लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' जैसे अनेक प्रेरक विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम पश्चात कार्यकर्ताओ की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान÷ के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों व नागरिकों से भेंट कर स्वदेशी उत्पादों के क्रय ङ्क विक्रय करने का अनुरोध किया एवं उनके प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी वस्तु अपनाने के संकल्प पत्र स्टीकर भी चिपकाएं व पत्रक वितरित किए।

पूर्व सैनिकों की जिला स्तरीय रैली, योजनाओं की दी जानकारी

वीर नारियों और युद्ध नायकों को किया सम्मानित

बैतूल। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के तत्वावधान में रविवार को गंज स्थित रामकृष्ण बगिया में पूर्व सैनिकों की जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारियां, शहीदों की पत्नियां और उनके परिजन शामिल हुए। समारोह के दौरान दो दर्जन से अधिक वीर नारियों और शहीदों की पत्नियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। रैली में उपस्थित

परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्व सैनिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। पेंशन, चिकित्सा और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर जिला अस्पताल और निजी संस्थाओं की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए, जबकि विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधाओं और ऋण योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के राष्ट्र के प्रति योगदान को नमन करते हुए किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और सैनिक कल्याण विभाग की ओर से उनके कल्याण के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया गया।

2 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ बैतूल रोड सड़क का निर्माण कार्य

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा धन्यवाद जीतू पटवारी

बैतूल/ मुलताई। मुलताई से बैतूल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग का आखिरकार 2 वर्ष बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। जिसमें नगरवासियों ने राहत की सांस ली है। परमंडल जोड़ से ड्रीमलैंड सिटी तक डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाली एक किलोमीटर सडक का निर्माण दो वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर रुका हुआ था, जिसके निर्माण का कार्य अब शुरू हुआ है।

सडक निर्माण प्रारंभ होने पर कोंग्रेसियों ने इसका श्रेय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिया है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी इसी सडक से मुलताई आए थे एवं उन्होंने इस सडक की दुर्दशा के लिए स्थानीय विधायक चंद्रशेखर देशमुख को जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद मुलताई में भाजपा एवं कांग्रेस के बीच जम कर बयानबाजी भी

हुई थी। रविवार को कांग्रेस नेता संजय यादव, किशोर सिंह परिहार, प्रहलाद सिंह ठाकुर, सुमित शिवहरे, अरुण यादव, अखिलेश फुलवार, लोकेश यादव, रितेश शर्मा, आशीष सोनी, अरुणेश मिश्रा, आशीष जैन सहित दर्जनों कांग्रेसी बैनर पोस्टर लेकर सडक निर्माण स्थल पर पहुंचे एवं निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता संजय यादव, किशोर सिंह परिहार ने बताया कि सडक़ निर्माण नहीं होने से सडक पर बडे-बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसके कारण इस सडक पर दुर्घटनाओं का अम्बार लग गया था एवं सैंकडो लोग इन दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल भी हो चुके है।

वृद्धजनों ने नर्मदा दर्शन व स्नान का लाभ पाया, पांचवी आनंद यात्रा महेश्वर में सम्पन्न

धार । भोज शोध संस्थान द्वारा 2017 से संचालित वृद्धजन स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प सुपर 60 प्लस की पांचवी आनंद यात्रा महेश्वर में सम्पन्न हुई। निदेशक डॉ दीपेंद्र शर्मा ने बताया कि ओंकारेश्वर, मोहनखेड़ा, भक्ताम्बर, मांडू के बाद इस यात्रा में जलकोठी सहस्त्रधारा, गायत्री पीठ आश्रम नर्मदा दर्शन स्नान का पुण्य लाभ महेश्वर का मिला। श्रद्धालय वृद्धाश्रम व सुपर 60 प्लस प्रकल्प के चुनिंदा वृद्धजनों ने विशेष बस से यह यात्रा की। प्रकल्प संयोजक दुर्गेश नागर ने बताया 41 वृद्धजनों ने इस यात्रा में भाग लिया। मंडलेश्वर स्थित आवासीय कन्या शिक्षा परिसर का अवलोकन किया। संत

सानिध्य गायत्रीपीठ के श्री ओमानंद जी महाराज का मिला। संतश्री जी जीवन आनंद के सूत्रों को साझा किया।

जीवन में आनंद बाहर नहीं हम सबके भीतर ही है। व्यर्थ का बोझ ना रखे। सदैव प्रसन्न रहे। संत श्री ने सुपर 60 प्रकल्प की सराहना की व वृद्धजनों को वर्षभर सेवा सहयोग कार्यों से जोड़ने का सुझाव दिया। इस सभा में वृद्धजनों की ओर से भागवंता बाई, नरवरसिंह ठाकुर ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। यात्रा में अशोक चौहान, दीपक गौड़, सुशील कुमार, गोविंद भाई, भगवान पाटीदार का सराहनीय योगदान रहा। जानकारी मीडिया प्रभारी रॉकी मक्कड़ ने दी।

बैतूल की लवी ने शास्त्रीय गायन से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध

बैतूल। ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह संगीत कला समिति द्वारा रवींद्र भवन भोपाल में आयोजित ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह संगीत समारोह का शुभारंभ बैतूल की नन्ही प्रतिभा लवी देशमुख ने शास्त्रीय गायन से किया। वहीं

यशवी देशमुख ने तबले पर लयबद्ध संगत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। दोनों की जुगलबंदी ने समारोह को यादगार बना दिया। समारोह में पंडित किरण देशपांडे और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के उप निदेशक शेखर करहाडक़र मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में बैतूल की नन्ही प्रतिभा लवी ने अपने मधुर स्वरों में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। लवी के गायन ने संगीतप्रेमियों को भावविभोर कर दिया। समारोह में इंदौर की रेवा भदौरिया ने वायलिन वादन में सधे हुए सुरों से माहौल को भावमय बना दिया, जिनकी तबले पर संगत यशवी देशमुख ने की।

बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर जयस चलाएगी 15 दिवसीय जनजागृति पखवाड़ा

बैतूल। रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम स्टेडियम में रविवार 26 अक्टूबर को जय आदिवासी युवा शक्ति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पूरे जिले में धूमधाम और गौरव के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर जयस ने घोषणा की कि जिलेभर में 1 नवंबर 14 नवंबर तक जयस जनजागृति पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में आदिवासी अस्मिता, एकता और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहेगा। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम 15 नवम्बर को आयोजित होगा, जिसमें जिले सहित प्रदेशभर से हजारों की संख्या में आदिवासी भाई-बहनों की

उपस्थिति रहने की संभावना है। इसी क्रम में जिले के सभी 10 ब्लॉकों में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे, जिनके लिए जयस द्वारा संबंधित ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बैठक की अध्यक्षता जयस जिलाध्यक्ष एड. संदीप कुमार धुर्वे ने की। इस अवसर पर जिला संरक्षक राजा धुर्वे, जिला प्रभारी महेश शाह उइके, जिला सचिव राजकुमार काकोडया, राजरावण परते, आईटी सेल प्रभारी रामदीन इवने, मीडिया प्रभारी सौरभ सलामे सहित विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाहपुर ब्लॉक से मिथलेश (बब्बा) उइके, भीमपुर से इंद्रकुमार उइके, चिचोली से शिवम उइके, आमला से गोविंद उइके एवं सुनील उइके, भैंसदेही से अशोक उइके, तुलसी उइके, अक्षय इवने, पतिराम उइके, शैलेन्द्र धुर्वे, अर्जुन धुर्वे, सचिन उइके, पिंटू पंद्रे सहित बड़ी संख्या में जयस कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बिरसा मुंडा जी की जयंती को आदिवासी एकता और गर्व का उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।

मध्यप्रदेश में 'ग्रोथ हब' पहल की शुरुआत इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए बनेगा समग्र मास्टर प्लान

रायसेन (निप्र)। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने के उद्देश्य से गुरुवार को मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक में 'ग्रोथ हब ' पहल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह महत्वाकांक्षी पहल नीति आयोग और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से इंदौर एवं भोपाल क्षेत्रों के लिए व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक विकास रणनीति तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सुश्री एना रॉय ने किया। कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष से कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सुविचारित आर्थिक योजना से न केवल इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी बल्कि अनियंत्रित शहरी विकास पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सुश्री एना रॉय ने बताया कि इंदौर और भोपाल आर्थिक क्षेत्रों के लिए समग्र आर्थिक मास्टर प्लान अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और नीति आयोग इस दिशा में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देगा।

'ग्रोथ हब' पहल के प्रथम चरण में इंदौर आर्थिक क्षेत्र (इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा) और भोपाल आर्थिक क्षेत्र (भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए आर्थिक प्रोफाइल, प्राथमिक परियोजना सूची और क्रियान्वयन रोडमैप तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में जबलपुर, सतना-रीवा, सागर और ग्वालियर क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान नीति आयोग ने G-Hub पहल का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया। संबंधित जिलों ने अपनी आर्थिक प्रोफाइल, प्रमुख अवसर, बाधाएँ और 90-दिवसीय कार्ययोजना साझा की। बैठक में स्टियरिंग कमेटी व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा में त्वरित कार्यों पर सहमति बनी जिनमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स , प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना, एंटरप्राइज सपोर्ट सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स-वेयरहाउसिंग, कौशल एवं अप्रेंटिसशिप, निवेश-प्रोत्साहन और एकीकृत मास्टर प्लानिंग जैसे बिंदु शामिल हैं।

यह पहल 'विकसित मध्यप्रदेश' के दृष्टिकोण से पूर्णतः संरेखित है जो नागरिकों को सुखद जीवन, संपन्न रोजगार अवसर और सांस्कृतिक गौरव प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। G-Hub कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना-आधारित क्रियान्वयन, नीति सरलीकरण, भूमि आपूर्ति, एकीकृत अवसंरचना और निवेश प्रोत्साहन के जरिये राज्य में उच्च वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण आजीविका और बेहतर 'ईज़ ऑफ लिविंग' सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री संजय कुमार शुक्ल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग श्री ऋषि गर्ग और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बीरन सिंह ने स्थापित किया स्वयं का कम्प्यूटर सेंटर

रायसेन (निप्र)। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक मजबूत सहारा है। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण राशि उपलब्ध करा रही है। रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम गुलगांव निवासी बीरन सिंह राजपूत भी उन हितग्राहियों में शामिल हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना रोजगार शुरू करने में मददगार साबित हुई है। हितग्राही बीरन बताते हैं कि उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा के बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी नहीं थी। ऐसे कठिन समय में उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में पता चला और उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सम्पर्क कर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त की और आवेदन प्रक्रिया भी जानीं। विभाग से योजना की जानकारी मिलने के बाद एमपी ऑनलाईन के माध्यम से कम्प्यूटर सेंटर शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया। विभाग द्वारा आवेदन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायसेन को भेजा गया। जहां बैंक प्रबंधक द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई और दस्तावेज पूर्ण होने पर 09 लाख रू का ऋण स्वीकृत एवं वितरित कर दिया गया। बैंक द्वारा प्राप्त राशि से सलामतपुर में कम्प्यूटर सेंटर स्थापित किया गया है। जिसमें अभ्यर्थियों को बेसिक कम्प्यूटर एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पॉवर प्वाइंट आदि सिखाया जा रहा है। बीरन सिंह द्वारा अपने कम्प्यूटर सेंटर पर दो लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तथा वह नियमित रूप से बैंक की किस्त जमा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत व्यवसाय स्थापित कराने के लिए बीरन सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है।

संक्षिप्त समाचार

कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों को देखने पहुंचे कलेक्टर और एसपी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कार्बाइड गन से प्रभावित व्यक्तियों से संवाद कर इलाज के संबंध में तमाम व्यवस्थाओं की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न ना हो के निर्देश मौके पर मौजूद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. मनीष निगम को दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कार्बाइड गन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों को हुए नुकसान और बच्चों की आंखों के इलाज के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के साथ साथ बच्चों को इलाज में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और उनके परिजन भी परेशान ना हो का विशेष ध्यान रखने के लिए मौके पर उपस्थित डॉक्टर और समस्त मेडिकल स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन मरीज के परिजनों को दिया है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर किया गया 460 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। जिले में 24 अक्टूबर को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 330 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 130 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही 50 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर बच्चों के टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।

किसान मंडी की व्यवस्था से संतुष्ट, बोले खरीदी कार्य सुचारू और पारदर्शी

सीहोर (निप्र)। भावांतर योजना के तहत शुरू हुई सोयाबीन खरीदी के दौरान किसानों ने मंडी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। अपनी उपज लेकर सीहोर कृषि उपज मंडी पहुंचे ग्राम पटनी के किसान श्री अवधेश सिंह मेवाड़ा और ग्राम कोलूखेड़ी के किसान श्री दुर्गा प्रसाद ने कहा कि मंडी में खरीदी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। दोनों किसानों ने बताया कि मंडी में तौल, पंजीयन और भुगतान की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों के बैठने, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था की गई है। किसानों ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की सराहना करते हुए कहा कि खरीदी कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार प्रशासन की तैयारियों और अधिकारियों की सतर्कता के कारण मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और भावान्तर योजना के तहत उन्हें अपने फसल का उचित मूल्य मिलेगा।

जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न

बैतूल (निप्र)। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मुलताई विधायक श्री चन्द्रशेखर देशमुख , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, जल संसाधन मंडल अधीक्षण यंत्री श्री विपिन वामनकर, जल संसाधन संभाग बैतूल कार्यपालन यंत्री श्री रोशन कुमार सिंह, जल संसाधन संभाग मुलताई कार्यपालन यंत्री श्री सी.एल. मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया कि वर्ष 2025-26 में जिले के कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने के कारण कुछ जलाशय अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं भर पाए हैं। बैतूल एवं मुलताई के दोनों जल संसाधन संभागों के अंतर्गत 07 मध्यम एवं 187 लघु सिंचाई योजनाओं में कुल 448.524 मि.घ.मी. क्षमता के विरुद्ध 410.991 मि.घ.मी. 92 प्रतिशत जल का भंडारण हुआ है। इससे जिले में 90 हजार 852 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। बैठक में यह निर्णय लिया कि 10 नवम्बर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा।

जिन जलाशयों में जल स्तर कम है, वहां एक पलेवा, एक पानी की नीति के अनुसार सीमित सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा झारकुंड जलाशय, मालसिवनी जलाशय, पचामा जलाशय, पाढर जलाशय में पानी अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप नहीं भरा है, जिससे इस वर्ष रबी फसलों के लिए सिंचाई नहीं की जा सकेगी।

सोयाबीन खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो संचालित - कलेक्टर

सीहोर जिले में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू

- कलेक्टर ने इछावर, भैरूंदा, गोपालपुर, राला एवं लाड़कुई मंडी की व्यवस्थाओं और खरीदी प्रक्रिया का किया निरीक्षण
- किसानों की समस्याओं का किया जाए त्वरित और प्रभावी निराकरण : कलेक्टर
- सभी पात्र किसानों को मिले भावान्तर योजना का लाभ - कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। सरकार की भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आज 24 अक्टूबर से जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन खरीदी कार्य प्रारंभ हो गया। खरीदी प्रक्रिया की सुचारू एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इछावर भैरूंदा, गोपालपुर, राला एवं लाड़कुई की कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने गोपालपुर मंडी के निरीक्षण के समय गोपाल रोड़ की मरम्मत के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने मंडी परिसर में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा कर सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया देखी। उन्होंने एसडीएम सहित सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि मंडी में उपज लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा न हो, इसके लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने मंडी सचिव, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र किसान भावांतर योजना के लाभ से वंचित न रहे। यदि किसी किसान को खरीदी कार्य से संबंधित कोई समस्या या शिकायत हो, तो उसका तत्काल और प्रभावी निराकरण किया जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपज तौल, पंजीयन, परिवहन, गुणवत्ता परीक्षण एवं भुगतान व्यवस्था की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि खरीदी कार्य में पूरी पारदर्शिता और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि मंडियों में पेयजल, विश्राम स्थल, तौल मशीन, परिवहन और सुरक्षा की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। खरीदी कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आमजन में जागरूकता लाना जरूरी

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आमजन में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। टीबी रोग किन कारणों से होता है और इनसे कैसे बचाव करें यह जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। टीबी रोग के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता रहेगी, तो पंचायत स्वत : टीबी रोग मुक्त हो जाएगी।स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टीबी का समय पर पता चल जाये और इसका पूरा उपचार हो जाए तो, यह पूरी तरह से रोकथाम और उपचार योग्य रोग है। टीबी को छुपाएं नहीं और न कोई भी व्यक्ति इसे बताने में संकोच न करे। सरकार इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए नि :शुल्क सुविधा प्रदान करती है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीबी की वैक्सीन लगायी जा रही है। टीबी मरीजों के उपचार, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था के साथ जन-जागरुकता के लिए व्यापक प्रचार- प्रचार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हथवांस से भोंखेडी-कुम्हाबड 4 करोड़ 92 लाख की लागत से बनेगी सड़क

सांसद विधायक ने किया भूमिपूजन आसपास गांवों के हजारों लोगों को होगी सहूलियत

नर्मदापुरम (निप्र)। पिपरिया नजदीकी ग्राम पंचायत हथवांस रामविलास कॉलोनी में शुक्रवार को एस.एच. 22 हथवांस हनुमान मंदिर से भोंखेडी-कुम्हाबड तक सड़क निर्माण कार्य, लम्बाई 5 किलोमीटर का भूमि पूजन किया गया।

यह मार्ग 4 करोड़ 92 लाख की लागत से बनेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी एवं पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, सोहागपुर विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने सबसे पहले भूमि पूजन किया और गेंती चलाकर काम प्रारंभ कराया। हथवांस में सड़क बनाए जाने को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधि विधान से पूजन कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी एवं सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए कहा कि गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो सरकार ने किया है। ग्रामीण लोगों को भी स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया है। गांव के विकास में ही देश का विकास छुपा है। इस सड़क के बन जाने से आसपास कई गांवों को सहूलियत मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी व प्रदेश में हमारी सरकार बनी तब से विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली सरकारों ने जनता के साथ छलावा किया और गांव में सडकें नहीं थीं। आने जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन आज हर जगह सड़कें बन गई हैं, या फिर बन रही हैं। ग्रामीणों द्वारा सड़क बनाने की मांग होती रही है। अब रामविलास कॉलोनी से भोंखेडी मार्ग तक पांच किलो मीटर सडक बनाई जानी है। आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, पिपरिया नगर पालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल, जनपद अध्यक्ष संध्या सिंगारे, जनप्रतिनिधि गोपाल दास दूदानी, अर्चना साहू, माधवदास अग्रवाल, राजा भैया पटेल, प्रशांत रघुवंशी, बलराम ठाकुर, प्रदीप कुमार पटेल, अरविंद राय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही।

शासकीय अस्पताल सुखतवा में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 94 लोगो की गई स्क्रीनिंग

नर्मदापुरम (निप्र)। शासकीय अस्पताल सुखतवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. नरसिंह गेहलोत के निर्देश पर मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

इस शिविर में कुल 94 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 11 पॉजिटिव रोगियों को दवा और परामर्श प्रदान किया गया। शिविर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाजिया सिद्दीकी द्वारा मनहित एप की जानकारी एवं उपयोगिता बताई गई तथा चिकित्सकों, स्टॉफ एवं मरीजों द्वारा मनहित एप डाउनलोड किया गया। शिविर में डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को किस तरह टोल फ्री नंबर 14416 से सहायता लेना है एवं जिला अस्पताल में स्थित मनकक्ष की पूर्ण जानकारी दी। आईईसी सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर बीएमओ डॉ. आर एस मीना, डॉ अंकित गौर मनकक्ष नोडल अधिकारी, एमओ डॉ.सतीश रघुवंशी, डॉ आसिया सिद्दकी, निधि पटवा, पवन मेहरा सहित अन्य स्टॉफ उपस्थित रहा।

सीहोर जिले के किसान श्री अवधेश सिंह सहित सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों को मिल रहा है योजना का लाभ

किसानों के हितों की रक्षक है सरकार की भावांतर योजना, योजना के तहत मंडियों में शुरू हो गई सोयाबीन की खरीदी

सीहोर (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना शुरू की गई है, ताकि किसानों को उनकी सोयाबीन की फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलने पर भी नुकसान न उठाना पड़े। योजना में किसानों के पंजीयन के पश्चात अब 24 अक्टूबर से भावांतर योजना के तहत मंडियों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई है। भावांतर योजना के तहत विक्रय के लिए अपनी उपज लेकर सीहोर कृषि उपज मंडी पहुंचे ग्राम पटनी के किसान श्री अवधेश सिंह मेवाड़ा बताते हैं कि इस वर्ष जब सोयाबीन के भाव को लेकर चिंता थी, तभी सरकार की भावांतर योजना उनके लिए राहत बनकर आई है। वे कहते हैं कि अब हमें यह चिंता नहीं कि मंडी में दाम कितना रहेगा, क्योंकि सरकार हमारी मेहनत का पूरा मूल्य सुनिश्चित कर रही है। किसान श्री अवधेश सिंह मेवाड़ा ने बताया कि वे योजना के तहत अपनी सोयाबीन की उपज मंडी में विक्रय कि लिए लेकर आए। उन्होंने बताया कि मंडी में तौल, पंजीयन और भुगतान की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों के बैठने, पेयजल एवं अन्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार मंडियों में किए गए प्रबंधों की किसानों ने सराहना करते हुए कहा कि खरीदी कार्य पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। किसान श्री अवधेश सिंह मेवाड़ा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने किसानों के भीतर नया आत्मविश्वास पैदा किया है। वे कहते हैं कि अब उन्हें विश्वास है कि उनकी तरह सभी किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा।

भावांतर योजना : एसडीएम ने कृषि मंडी बडोरा का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। राज्य सरकार की किसान हितैषी भावांतर भुगतान योजना के तहत शुक्रवार से जिले में सोयाबीन फसल की खरीदी प्रक्रिया शुरू हुई। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार योजना के तहत प्रथम दिन एसडीएम श्री अभिजीत सिंह ने कृषि उपज मंडी समिति बडोरा के खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा गठित अनुभाग एवं मंडी स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एसडीएम श्री सिंह ने मंडी सचिव एवं स्टाफ को भावांतर योजना के क्रियान्वयन में शासन के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी कार्य में पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राइट क्लिक

बिहार- चुनाव कोई भी जीते, नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं...

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार जैसे-जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक समीकरण ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) और घोषणाओं की रेवड़ी के इर्द-गिर्द सिमटते जा रहे हैं। यूं भी बिहार देश में जातिवादी राजनीति का सबसे बुरा उदाहरण है। यानी बात भले ही विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, सामाजिक भेदभाव आदि तमाम मुद्दों से शुरू हो, लेकिन अंतत: जाति पर ही आ टिकती है। वही इस बार भी रहा है। सभी पार्टियों ने टिकट इसी आधार पर बांटे हैं। इसके अलावा बीते 20 सालों से राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार एक जरूरी फैक्टर हैं। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री वही रहते हैं।

हालांकि महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर एनडीए से अपने नेता घोषित करने की चुनौती दी है, लेकिन यह कांच की तरह साफ है कि गठबंधन कोई-सा भी जीते, सीएम नीतीश ही होंगे। यह बात उस भाजपा की भी समझ आ गई है, जो कुछ समय पहले तक पिछले दरवाजे से नीतीश की जगह किसी भाजपा के चेहरे को सीएम बनाने का सपना देख रही थी। कारण साफ है, नीतीश उसी पाले में रहेंगे, जो उन्हें सीएम बनाएगा और नीतीश की पार्टी के बगैर कोई गठबंधन सरकार बना ले, यह लगभग नामुमकिन है। फिर नीतीश को राज्य में ईबीसी का समर्थन मिलता रहा है। यूं अब विपक्षी राजद नीत महागठबंधन ने भी ईबीसी दांव चलते हुए मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। जिसके जवाब में भाजपा और एनडीए ने बिहार के कद्दावर ईबीसी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर का नाम जपना शुरू कर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि बिहार में बाकी जातियों की पार्टी प्रतिबद्धता लगभग तय है कि अब ईबीसी वोट बैंक को जो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, वह सरकार बनाने में सफल होगा। गौरतलब है कि राज्य में नीतीश की ईबीसी राजनीति की काट के तौर पर ईबीसी से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का दावेदार घोषित किया है। भाजपा के पास कोई बड़ा ईबीसी चेहरा नहीं है। हालांकि यह मान लेना कि मुकेश सहनी के चलते सभी ईबीसी जातियां महागठबंधन के साथ हो जाएंगी, केवल अतिआशावाद है। गौरतलब है कि बिहार में ओबीसी की कुल 146 जातियां हैं। इनमे से अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की संख्या 113 है। इनमें 23 मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। यह राज्य में कुल ओबीसी आबादी का करीब 60 प्रतिशत है। इसी से इस वर्ग की वोट महत्ता को समझा जा सकता है। पिछले कई सालों से यह वोट बैंक मोटे तौर नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन उनके बार-बार पाला बदलने से इसमें कुछ सेंध लगी है। फिर भी यह वोट बैंक नीतीश से छिटक जाएगा, इसकी संभावना कम है।

हालांकि खुद नीतीश उस कुर्मी समाज से आते हैं, जो ओबीसी कृषक जाति है। लेकिन नीतीश ने कुर्मियों के साथ कुशवाह जाति का भी एक लव-कुश समीकरण बनाया हुआ है। दूसरे, इसी जाति के एक और नेता उपेन्द्र कुशवाहा भी इस बार एनडीए के साथ हैं। अगर वोटों के जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो एनडीए में ज्यादा पुख्ता स्थिति दिखती है। दूसरे, इस बार एनडीए में नीतीश की जद-यू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ रही हैं। साथ ही पिछले विस चुनाव में नीतीश की पार्टी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाले चिराग पासवान की पार्टी इस बार एनडीए में है। ऐसे में जद-यू का स्ट्राइक रेट इस बार बेहतर रहने की उम्मीद है। ऐसे में कोई भी गठबंधन नीतीश को माइनस कर सरकार नहीं बना पाएगा। उधर महागठबंधन में राजद के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। जिस तरह वह हर मामले में वह तेजस्वी के आगे सरेंडर होती दिख रही है और जिस तरह पिछले माह वोट चोरी के खिलाफ माहौल खड़ा करने के बाद पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बिहार से दूरी बना ली है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस को बिहार से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। हालांकि राहुल चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे राहुल गांधी ने पिछले दिनो एक विशेष घोषणा पत्र जारी कर कहा था कि अगर वह सत्ता में आई तो स्थानीय निकायों में ईबीसी आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करेगी। कुछ लोगों को भी भी शंका है कि नीतीश चुनाव बाद फिर पाला बदल सकते हैं, लेकिन तब भी सीएम वही रहेंगे, समझौता इसी शर्त पर होगा। वैसे पिछले साल से नीतीश लगातार यह कहते रहे हैं कि वो अब 'इधर-उधर' कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनका मन राजनीतिक रूप से चंचल रहता है। अगर चुनाव में एनडीए सत्ता में लौटता है तो भी नीतीश को ही सीएम बनाना मजबूरी होगी, क्योंकि जद-यू किसी और के नाम पर शायद ही राजी हो। तेजस्वी यादव को महागठबंधन द्वारा अपना सीएम दावेदार घोषित करने और एनडीए पर भी अपना दावेदार घोषित करने का दबाव बनाने के बाद भाजपा की भी मजबूरी हो गई है कि वह नीतीश का बचाव करे। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने हाल में कहा कि 'एनडीए में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है।' इसका सीधा अर्थ यह है कि एनडीए जीता तो सीएम नीतीश ही होंगे। भले ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हों। नीतीश की फिटनेस को लेकर दूसरों को भले शंका हो, लेकिन नीतीश अपनी राजनीतिक चालें बहुत सोच-समझ कर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। लिहाजा उन्हें साइड लाइन करना टेढ़ी खीर है। राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा तेज है कि चुनाव में एनडीए की जीत के बाद फिलहाल तो नीतीश ही सीएम बनेंगे। लेकिन बाद में भाजपा उन्हें किसी तरह हटाकर अपना सीएम बनाना चाहेगी। लेकिन यह भी टेढ़ी खीर है। क्योंकि अव्वल तो नीतीश पद छोड़ेंगे ही क्यों? दूसरे, अगर वो किसी तरह तैयार भी हो जाएं तो उनका समुचित पुनर्वास भाजपा कहां और कैसे करेगी? केन्द्र सरकार में कोई ऐसा शीर्ष पद खाली नहीं है। नीतीश राज्यपाल बनकर राजनीतिक वनवास में जाने के लिए शायद ही तैयार हों, क्योंकि बिहार की सियासत में उन्हें अपनी हैसियत का पूरा अंदाजा है। कई बार उनके असहज करने वाले आचरण को छोड़ दें तो नीतीश राजनीतिक रूप से सौ फीसदी सचेत और सक्रिय हैं। उन्हें किसी तरह सीएम पद से हटा दिया भी जाए तो उनका विकल्प क्या है? इस मायने में 'राजनीति की नीतीश शैली' अपने आप में अनोखी है। उन्हें न तो किसी से परहेज है और न ही किसी के वो बंधुआ हैं। वैचारिक प्रतिबद्धताएं उनके लिए बेमानी हैं। अपनी शर्तों पर जोड़ तोड़ राजनीति की नीतीश थ्योरी का बुनियादी उसूल है। उनका सिद्धांत यही है कि सत्ता हाथ में हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कुर्सी वैध और अवैध की दुविधा को बेरहमी से कुचल देती है। यही नहीं, नीतीश ने खुद अपनी पार्टी तो दूर, सहयोगी पार्टियों में भी अपना कोई विकल्प खड़ा होने नहीं दिया है। बीच में उनके इकलौते बेटे निशांत को चुनाव लड़वाने की बात चली थी। लेकिन नीतीश ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार शुरू होते ही उन्होंने पहला हमला लालू के परिवारवाद पर किया। जाहिर है कि बिहार के राजनीतिक फलक से नीतीश तभी हटेंगे, जब वो खुद चाहेंगे या फिर ईश्वर की वैसी इच्छा रही तो। वरना बिहार की राजनीति में नीतीश अपरिहार्य हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि नीतीश बहुत विनम्रता और ठंडे दिमाग के साथ सियासी पांसे चलते और प्रतिद्वंद्वी को मात देते हैं। इस मुकाबले तेजस्वी अभी 'बच्चे' हैं। यद्यपि बिहार में हर परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देने और जीविका दीदियों का मानदेय तीन गुना बढ़ाने जैसी सनसनीखेज लेकिन अव्यावहारिक घोषणाएं करके तेजस्वी ने बड़ा दांव चला है। इससे कुछ युवा प्रभावित हो सकते हैं। अव्यावहारिक इसलिए कि जानकारों के अनुसार तेजस्वी ने अकेले जो वादे कर डाले हैं, उसे पूरा करने के लिए बिहार सरकार के दो वार्षिक बजटों की राशि भी कम पड़ेगी। अगर सचमुच ढाई करोड़ लोग अकेले बिहार में सरकारी नौकरी में रख भी लिए तो वो करेंगे क्या? क्योंकि पूरे देश में केन्द्र, राज्य के सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या भी ढाई करोड़ नहीं होती। दूसरी तरफ नीतीश की कितनी ही आलोचना की जाए, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा प्रतिबद्ध वोट महिलाओं का है, जो कुल वोटरों की संख्या का आधा है। मोटे पर महिला, ईबीसी और भाजपा के कारण अगड़ी जातियों का वोट अगर तय गणित के हिसाब से पड़ गया तो एनडीए की सरकार बनने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। नीतीश हटे भी तो केवल एक स्थिति में कि जब बिहार में उन्हें हटाने की आंधी चल जाए। ऐसा कोई अंडर करेंट है, लग नहीं रहा। वैसे सत्ता के खेल में दो और घटक अहम हैं। ये हैं असदुद्दीन औवेसी की एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन सुराज की पार्टी। यह किसका खेल बिगाड़ेंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश का तोड़ वो भी नहीं हो सकते।

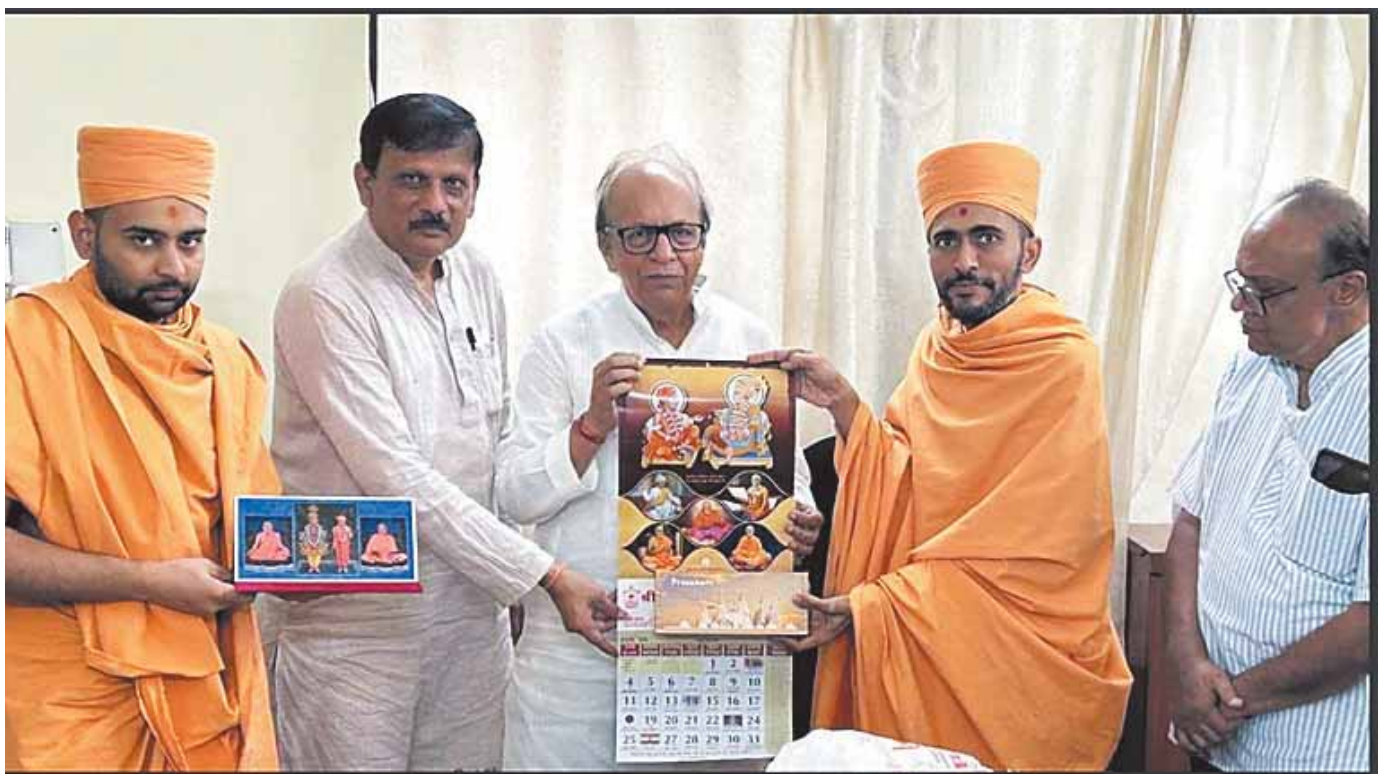

भोपाल। बीएपीएस अधरधाम मंदिर इंदौर के प्रभारी विमल सेवा स्वामी और उनके सहयोगी स्वामीजी ने रविवार को तुलसी नगर स्थित श्री ऑरो मंदिर के दर्शन किए तथा श्री ऑरोबिंदो स्कूल का अवलोकन किया। विमल सेवा स्वामीजी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी धर्म सेवा कर चुके हैं। इस अवसर पर 'दैनिक सुबह सवेरे' के प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी ने स्वामीजी को अखबार की प्रति भी भेंट की, जिस पर स्वामीजी ने कृपापूर्वक अपने हस्ताक्षर किए। इस दौरान 'सुबह सवेरे' के कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल, मप्र संपादक विनोद तिवारी तथा स्कूल के सहकर्मी मौजूद थे। स्वामीजी ने इस प्रसंग पर सभी को स्वामीनारायण संस्था द्वारा प्रकाशित नव वर्ष पंचांग तथा प्रसादी प्रदान की।

पीएम मोदी ने अपने कार्यों और नवाचारों से देश में किया सकारात्मक ऊर्जा का संचार : मुख्यमंत्री

मन की बात कार्यक्रम-विविधता से भरे भारत का प्रस्तुत करती है लघु रूप

कोटरा स्थित कमला नेहरु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों को दिलाई स्वदेशी की शपथ

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात के प्रसारण का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोटरा सुल्तानाबाद स्थित कमला नेहरु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निवासियों के साथ श्रवण किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को स्वदेशी की शपथ दिलाई। मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने कार्यों और नवाचारों के आधार पर देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। मन की बात कार्यक्रम भारत का लघु रूप प्रस्तुत करती है। विविधता से भरे देश के विभिन्न राज्यों में क्या नया हो रहा है, यह इस कार्यक्रम से संक्षेप में ज्ञात होता है।

राज्यों के कई नवाचार अनुकरणीय और प्रेरक होते हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज के मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं की बढ़ती रूचि का विशेष रूप से उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर गुजरात में केवड़िया धाम पर्यटन के सुंदर और आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार का दल भी इन कार्यक्रमों में सहभागिता करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय परिवार परम्परा की सशक्त अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य की प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम पूर्ण भव्यता के साथ 5 मंचों पर किया जाएगा।

पीएम ने बीएसएफ के ग्वालियर डॉग ट्रेनिंग सेंटर का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की 127वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय नस्ल के श्वानों (डॉग्स) के बढ़ते उपयोग पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 5 वर्ष पहले उन्होंने भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाने की अपील की थी और अब इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय नस्ल के श्वान हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढल जाते हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है। पीएम ने ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का जिक्र किया।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नए साल में खिसका

कहते हैं रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब 2026 में ही लागू होगा। पहले नवंबर से अमलीजामा पहनाने की कोशिश थी, लेकिन खाका तैयार नहीं हो पाने के कारण मामला आगे खिसक गया। देश के अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का अमल होना तो तय है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का श्रेय लेना चाहेंगे। राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नर सिस्टम की चर्चा काफी पुरानी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखने में सहज और सरल हों, पर निर्णय लेने में तो सख्त हैं। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री समेत 13 की जगह 14 मंत्री करके तो यह दिखा ही दिया। डॉ. रमन सिंह और भूपेश बघेल के राज में सरकार 13 मंत्रियों से चली। विष्णुदेव साय ने राज्य में 14 मंत्रियों की नींव रख दी है तो वह आगे भी चलता ही रहेगा। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से अपराध पर कितना नियंत्रण पाया जा सकता है और कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है, यह तो समय बताएगा। इस प्रणाली के लागू होने से राजधानी का स्टेटस जरूर बढ़ जाएगा और महानगर जैसा हो जाएगा। बताते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए अभी अन्य राज्यों का अध्ययन ही चल रहा है। खाका सामने आने के बाद साफ़ होगा कि पुलिस कमिश्नर एडीजी स्तर का होगा या आईजी स्तर का। पर अभी से कई आईपीएस दावेदारी में लगे हैं। राजधानी के पहले पुलिस कमिश्नर का तमगा किसे मिलता है, इसका सबको इंतजार है। कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पद के बहाने ही कई आईपीएस का भला हो जाएगा।

मोना सेन की छलांग

भाजपा की नेता मोना सेन को इंतजार का मीठा फल मिल गया। राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनने के बाद भी कुर्सी नहीं मिली तो उन्हें राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष पद से नवाज दिया गया। मोना सेन का फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष बनने से ज्यादा चर्चा बनाने वालों की हो रही है। भाजपा के भीतर लोग मोना सेन की रहनुमा को तलाश रहे हैं। डॉ रमनसिंह के कार्यकाल में मोना सेन, राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कहते हैं तब मोना सेन को पद दिलाने के लिए भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों ने सिफारिश की थी। बताते हैं मोना सेन को उनकी पसंद का पद मिल गया है। गीत -संगीत से उनका वास्ता रहा है। सरकार ने केदारनाथ गुप्ता और श्रीनिवास राव मद्दी के बाद मोना सेन का ताज बदला है। श्रीनिवास राव मद्दी को पहले राज्य वित्त आयोग और केदारनाथ गुप्ता को दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में श्रीनिवास राव मद्दी को वेबरेज कार्पोरेशन और केदारनाथ गुप्ता को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया।

माइनिंग के धंधे में उतरे विधायक जी

कहा जा रहा है कि माइनिंग के धंधे में भाजपा के एक विधायक उतर आए हैं। विधायक जी नीलामी में बस्तर अंचल का एक खदान ख़रीदा है। इसमें एक रिटायर्ड वन अफसर भी उनके पार्टनर हैं। कांग्रेस के राज में यह माइंस कांग्रेस के बड़े नेता को आवंटित हुआ था। कांग्रेस के नेता माइंस का दोहन कर पाते, उससे पहले उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और वे अपने आप को बचाने में लग गए और माइंस लावारिस हो गई। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बाजी पलट गई। माइंस का कोई दावेदार न होने के कारण सरकार ने लीज रद्द कर दोबारा नीलामी कर दी। इसमें भाजपा के विधायक ने भाग्य आजमाया और उन्हें सफलता मिल गई।

बिल्डर के एम्प्लाई के चौके-छक्के

कहते हैं जमीन के बड़े-बड़े सौदे करने में अब तक तो बिल्डरों को ही माहिर खिलाड़ी माना जाता था, पर आजकल जमीन के सौदे में चौके-छक्के लगाने वालों में राज्य के एक नामी बिल्डर के मैनेजर का नाम आने लगा है। अब मैनेजर साहब बिल्डर के लिए सौदे कर रहे हैं या वे भी धंधे में उतरने वाले हैं, इसकी खोज चल रही है। मजेदार बात तो यह है कि मैनेजर साहब सौदों में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। कुछ अफसरान के काले को सफ़ेद करने में लगे हैं। चर्चा है कि काले को सफ़ेद करवाने में पुरुष अफसर ही नहीं, महिला अफसर भी पीछे नहीं हैं। खबर है कि इस काम में मैनेजर को मालिक का भी आशीर्वाद है।

कौन बनेगा महासमुंद का एसपी

महासमुंद के एसपी आशुतोष सिंह प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में जा रहे हैं। भारत सरकार ने आदेश कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आशुतोष सिंह की जगह अभी तक किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं की है। सरकार ने 24 अक्टूबर को सात आईपीएस की पोस्टिंग में हेरफेर किया। चार एसपी भी इधर से उधर हुए, पर महासमुंद अछूता रहा। अब महासमुंद का एसपी किसे बनाया जाता है, यह चर्चा का विषय है। पहले राज्यपाल के एडीसी सुनील शर्मा का नाम चर्चा में था, पर सुनील शर्मा की जगह जिन्हें एडीसी बनाया गया था, उन्होंने अब तक चार्ज नहीं लिया है और न ही किसी अन्य की पोस्टिंग हुई है। वैसे बताते हैं कि महासमुंद के एसपी के लिए तीन नामों पर विचार चल रहा है, जिसमें टॉप पर सुनील शर्मा का नाम है। सुनील शर्मा 2017 बैच के आईपीएस हैं। माना जा रहा है कि महासमुंद एसपी की पोस्टिंग के साथ कुछ और जिले प्रभावित हो सकते हैं।

लालच ने उलझाया कारोबारी को

जिसकी सरकार, उसकी नाव में सवार होने में माहिर राजधानी के कारोबारी इस बार जमीन के खेल में उलझ गए हैं और पुलिस से बचते फिर रहे हैं। मामूली सरकारी मुलाजिम से कई धंधों के मालिक बनने वाले कारोबारी के बारे में कहा जाता है कि वे किसी की जमीन पर अपनी तख्ती लगाकर उसे हथियाने के खिलाड़ी हैं। कहते हैं साल 2023 में कारोबारी ने एक निजी स्कूल के शिक्षक की जमीन पर कब्ज़ा कर लिया तो शिक्षक को दिल का दौरा पड़ गया। कांग्रेस राज में कारोबारी के खिलाफ कुछ लोगों ने धरना भी दिया था, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सत्ता के एक करीबी अफसर से दोस्ती के कारण वह बच गया। कारोबारी ने अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए ताकतवर अफसर के रिश्तेदारों को भी अपने खेल में शामिल कर लिया था। पिछली सरकार में इस कारोबारी का नाम शराब के खेल में आया था। ईडी के छापे भी पड़े थे, पर तब किस्मत ने साथ दे दिया था। इस बार फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ऐसे उलझे हैं कि मुंह छिपाना पड़ रहा है। कहते हैं न 'बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी', ऐसा ही कुछ कारोबारी के साथ दिखाई पड़ रहा है।

राज्योत्सव के बाद बदलेंगे कलेक्टर?

चर्चा है कि राज्योत्सव के बाद कुछ जिलों के कलेक्टर इधर से उधर होंगे। खबर है कि पांच नवंबर के बाद छह-सात जिले के कलेक्टर बदल सकते हैं। इसमें रायपुर, सरगुजा, बेमेतरा, कोरबा समेत कुछ अन्य जिलों के कलेक्टर बदले जाने की सुगबुगाहट है। बताया जा रहा कि जिले में फेरबदल के साथ मंत्रालय में भी कुछ सचिवों का विभाग बदल सकता है। कुछ निगम-मंडल के प्रबंध संचालक भी प्रभावित हो सकते हैं। संभाग आयुक्त की भी पोस्टिंग बदल सकती है। एक-दो संभाग आयुक्त मंत्रालय में वापसी चाहते हैं।